राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHI/2011/38334 वर्ष: 11 अंक: 170 पृष्ट : 08, नई दिल्ली, शनिवार, 01 जनवरी 2022 मूल्य: 1.50/-

ख़ास ख़बर

पीएम मोदी कल मेरठ में मेजर ध्यान चंद खेल विवि की आधारशिला रखेंगे

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी दो जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यान चंद खेल विवि की आधारशिला रखेंगे।यह खेल विवि मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांवों में 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। पीएमओ ने कहा, पीएम देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।

कंगना की याचिका सत्र अदालत ने की खारिज

मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले के स्थानांतरण का अनुरोध करने वाली अभिनेत्री की अर्जी खारिज करने के निचली आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को निरस्त कर दी। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.यू. बघेले द्वारा जारी विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

सपा एमएलसी सहित अन्य इत्र व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के इत्र व्यापारियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापा मारा जिनमें सपा के कन्नौज से एमएलसी का परिसर भी शामिल हैं। यह कार्रवाई कर चोरी की जांच के सिलसिले में की गई है। कन्नौज, कानपुर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सूरत, मुंबई और अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। करीब 30 से 40 परिसरों में यह कार्वाई की गई है। करीब एक दर्जन परिसरों में छापेमारी की कार्रवाई की गई।

जरा हट के... बग्गा

ओमीक्रोन का कसता शिकंजा

ओमीक्रोन के मामलों ने डेल्टा स्वरूप की जगह लेना शुरू कर दिया है: सूत्र

■ नई दिल्ली

देश में कोरेना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप ने अब मामलों की संख्या के मामले में डेल्टा स्वरूप की जगह लेना शुरू कर दिया है और संक्रमित पाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से अब लगभग 80 प्रतिशत ओमीक्रोन से संक्रमित मिल रहे हैं। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को दी।सूत्रों ने बताया कि हालांकि, सामने आने वाले मामलों में से एक तिहाई हल्के लक्षण वाले होते हैं जबकि बाकी बिना लक्षण वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमीक्रोन के कुल।,270 मामलों का पता चला है।कोविड-19 जांच में काफी कमी को देखते हुए, केंद्र ने बृहस्पतिवार को 19 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों से व्यापक पैमाने पर जांच करने का आग्रह किया था ताकि संक्रमित मामलों की तुरंत पहचान की जा सके और ओमीक्रोन स्वरूप के प्रसार को सीमित किया जा सके।

दो दिसंबर को देश में ओमीक्रोन स्वरूप के पहले दो मामलों की घोषणा किए जाने के बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय एक मिशन मोड में काम कर रहा है और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर राज्यों का लगातार मार्गदर्शन कर रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नियमित रूप से देश भर में कोविड-19, ओमीक्रोन की स्थिति और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठकें कर रहे हैं।

पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नियमित रूप से देश भर में कोविड-19, ओमीक्रोन की स्थिति और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठकें कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया विशेषज्ञ टीमों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा करते हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर रूम चौबीस घंटे काम कर रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर रूम चौबीस घंटे काम कर रहा है और सभी रुझानों और बढ़ोतरी का विश्लेषण कर रहा है तथा देशव्यापी स्थिति की निगरानी कर रहा है। जांच बढ़ाने, अस्पताल की तैयारियों को मजबूत करने, टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने तथा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना पर ध्यान दे रहा है।

राहुल गांधी ने टीकाकरण का लक्ष्य चूकने पर केंद्र की आलोचना की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी पात्र लाभार्थियों को इस साल के अंत तक कोविड-19 रोधी टीके की पूरी खुराक देने का वादा पूरा न करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की शुक्रवार को आलोचना की। सरकार ने जून में उच्चतम न्यायालय में कहा था कि उसे इस साल के अंत तक पूरी पात्र आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की खुराक देने की उम्मीद है। गांधी ने ट्वीट किया, केंद्र ने 2021 के अंत तक सभी को टीकों की दो खुराक देने का वादा किया था। आज इस साल का आखिरी दिन है। देश अब भी टीके से दूर है। एक और जुमला चकनाचूर। देश भर में शुक्रवार दोपहर तक टीके की 144.67 करोड़ खुराकें दी गईं। 84.51 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने टीके की पहली खुराक ले ली है जबकि 60.15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने दोनों खुराक ले ली है। 18 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों की कुल संख्या 94 करोड़ है।

फ्री टेस्ट के नाम पर ठगी, गृह मंत्रालय ने चेताया

कोरोना काल में साइबर अपराध के मामलों में काफी इजाफा हुई है। साइबर ठग लागातार लोगों को ठगने के फिराक में रहते हैं। अब उन्होंने कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट के नाम पर लोगों ठगना शुरू कर दिया है। मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध को लेकर एडवाइजरी जारी की है। देश में नए स्ट्रेन का मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में साइबर ठग लोगों को ओमिक्रोन वैरिएंट से संक्रमण का पता लगाने के लिए फ्री टेस्टिंग के नाम पर ठगना शुरू कर दिया है।

2022 सुस्वागतम्

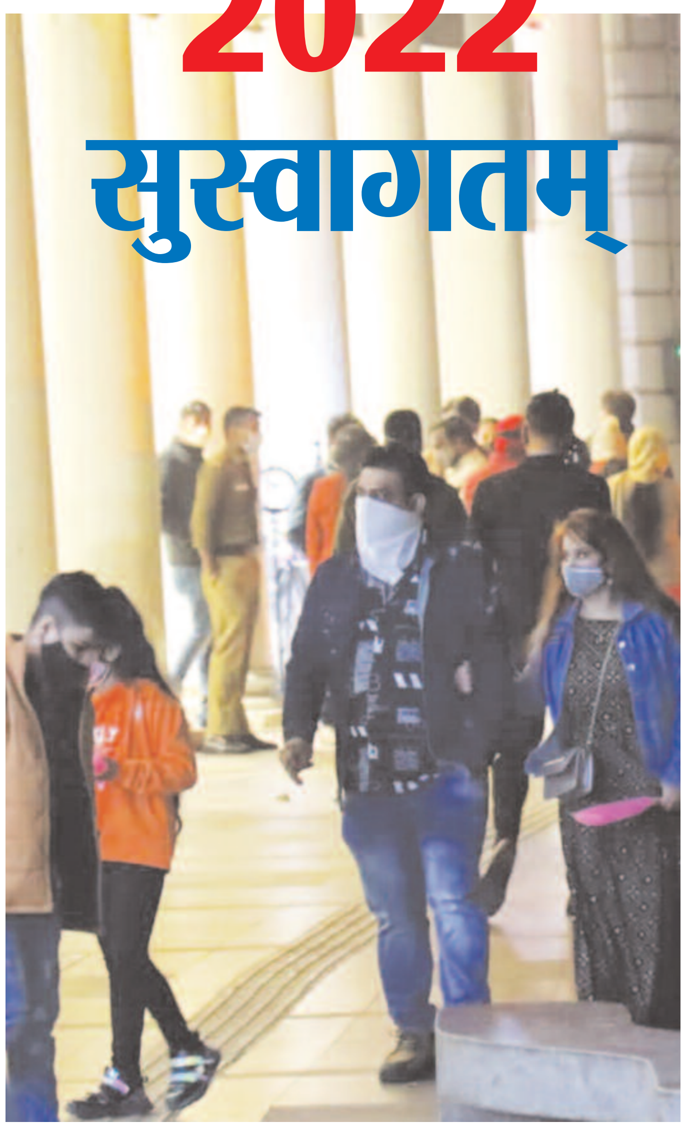

वेलकम 2022

दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोविड नियमों का पालन करते हुए नाइट कर्फ्यू से पहले ही युवा जोड़ों ने नए साल का जश्न मनाया।

बघेल ने गांधी विरोधियों पर निशाना साधा, बोस-टैगोर का हवाला दिया

■ रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कालीचरण महाराज पर निशाना साधते हुए लोगों को समाज में नफरत फैलाने वालों से सावधान किया। महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए बघेल ने कहा कि रवींद्र नाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियां भी गांधी की प्रशंसक थी। बघेल ने कहा कि टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा जबकि वैचारिक मतभेद के बावजूद बोस ने 1944 में रंगून से रेडियो पर अपने संबोधन में गांधी को राष्ट्रपिता कहा। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित गांधी हमारे अभिमान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। बघेल ने कहा और ए टटपूंजिए लोग गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इंकार करते हैं। तुम हो कौन? क्या तुम सुभाष बाबू से भी बड़े हो? क्या ए लोग टैगोर को नहीं मानते? कालीचरण को गालीचरण के तौर पर संदर्भित किया। कुछ लोग हैं जो समाज को घृणा से भर देना चाहते हैं। नफरत की फसल उगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आज कोरोना महामारी के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पंजाब: शहीद सैनिक के परिवार को 50 लाख, सरकारी नौकरी की घोषणा

■ चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने शुक्रवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवान जसबीर सिंह (26) के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए सिंह का प्रबल समर्पण उनके साथियों को अपने कर्तव्य को और अधिक समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए प्रेरित करेगा। सिंह पंजाब के तरन तारन जिले के वैन पॉइन गांव के रहनेवाले थे।उनके परिवार में उनके माता-पिता, एक भाई और एक बहन है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सिंह जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग और कुलगाम जिले में से एक में आंतकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। इसमें दो पाकिस्तानी नागरिकों समेत छह आतंकवादी मारे गए।

ओवैसी की गिरफ्तारी पर 22 लाख रुपए देने की घोषणा

■ गुरुग्राम

हिंदू धर्म गुरु कालीचरण महाराज की रिहाई की मांग को लेकर कई दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्य शुक्रवार को यहां सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए 22 लाख रुपए के नकद इनाम की भी घोषणा की। कुछ दिनों पहले रायपुर में धर्म संसद के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बृहस्पतिवार को कालीचरण को गिरफ्तार किया था।

बड़ी संख्या में दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ता उपायुक्त के आवास के सामने टैंक पार्क में एकत्र हुए और कालीचरण की रिहाई और ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय तक मार्च किया। उन्होंने कहा कि वे संतों और अन्य धार्मिक हस्तियों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू नेता और अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है।

घाटी में लोगों को भड़का रहे हैं कुछ नेता

■ श्रीनगर

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने घाटी में मुख्यधारा के नेताओं पर लोगों को उकसाने की कोशिश करने के लिए शुक्रवार को निशाना साधा। कुमार ने साथ ही यह भी कहा कि नेताओं या मीडिया को पुलिस जांच को गलत करार देने का कोई अधिकार नहीं है और केवल अदालत ही यह तय कर सकती है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक कुमार ने कश्मीर जोन पुलिस की उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने के लिए यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नेताओं से कहा कि वे जनता को भड़काने और युवाओं को बर्बाद करने में लिप्त न हों। कुमार ने कहा कि 2021 में घाटी की स्थिति में सुधार हुआ है, जो मुख्यधारा के कुछ नेताओं या कुछ मीडियाकर्मियों के दावे के विपरीत है। उन्होंने कहा, कुछ राजनीतिक दल के नेता, मीडिया का एक वर्ग, यह कहते रहते हैं कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया है कि स्थिति 1990 के दशक जैसी है।

जमीनी हकीकत से पता चलता है कि वे जो कह रहे हैं वह गलत है। स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पिछले साल कश्मीर में 238 आतंकी घटनाएं हुईं थीं, जबकि इस साल 192 आतंकी घटनाएं हुईं। पिछले साल मारे गए नागरिकों की संख्या 37 थी, जबकि इस साल यह 34 है, जबकि आतंकवादियों ने खुलेआम कहा था कि वे नागरिकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों की हत्या करेंगे।

बफरजोन में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत

चंद्रपुर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले स्थित ताडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य में बाघ के हमले में 23 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। वन अधिकरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना रिजर्व के मुल बफर रेंज के करवान बीट में दोनी गांव के नजदीक बृहस्पतिवार को हुई और शव आज सुबह मिला। मुख्य वन संरक्षक डॉ.जीतेंद्र रामगांवकर ने बताया कि मृतक की पहचान भरत रामदास कोवे के तौर पर हुई है और वह दोनी गांव का रहने वाला था।

नफरत की दुर्गंध फैला रही है भाजपा : सपा

■ कन्नौज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राजनीति को दूषित किया है और ए नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं।सपा प्रमुख ने शुक्रवार को कन्नौज में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन के यहां छापेमारी के कुछ घंटों बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, भाजपा के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं और इन्होंने राजनीति को दूषित किया है, ये नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं, ये सौहार्द और सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। उन्होंने कहा, नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भाजपा के लोग हैं जानबूझकर समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, ए कन्नौज को भी दुनिया भर में बदनाम करने में लगे हैं। यादव ने एक नारा दिया अब इत्र का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि राम मंदिर का निर्माण कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हो रहा है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राजनीति को दूषित किया है और ए नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं।

सरकारी पैसे से हो रही रैलियों में लगातार झूठ बोल रहे शाह : कांग्रेस

■ लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को सरकारी पैसे से आयोजित किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैलियों में लगातार झूठ बोल रहे हैं। लल्लू ने दावा किया, सरकारी पैसे से हो रही रैलियों में गृह मंत्री अमित शाह लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी की रैलियों में जनता के सरोकार वाले मुद्दों की बजाय अनर्गल बातें हो रही है जिसका उत्तर प्रदेश के विकास से कोई वास्ता नहीं है। अमित शाह परिवारवाद, पक्षपात और पलायन की बात कर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि भाजपा टिकट बंटवारे में तीस प्रतिशत भागीदारी भाजपा नेताओं के परिवार वालों को देती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट देने जा रही है। शाह उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाने के लिए पांच साल के लिए और मांग रहे हैं, जबकि पिछले पांच सालों में प्रदेश अपराध, महिला अत्याचार और बेरोजगारी में नंबर वन बना है। अगर एक बार और भाजपा सरकार आ गई तो बेरोजगारी की वजह से युवाओं का पलायन और बढ़ेगा , क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछले पांच साल में कोई ऐसा सरकारी उपक्रम नहीं लगाया जिसमें रोजगार दिया जा सके।

चेल्लाकुमार पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा सदस्य ए. चेल्लाकुमार को पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) का प्रभारी नियुक्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जून में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के पार्टी प्रभारी का पद खाली हो गया था। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि चेल्लाकुमार ओडिशा के पार्टी प्रभारी की मौजूदा जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। चेल्लाकुमार तमिलनाडु के कृष्णागिरि से लोकसभा सदस्य हैं।

मांग | उच्चतम न्यायालय में दाखिल की याचिका

नफरत भरे भाषण: अदालत की निगरानी में हो जांच

एजेंसी ■ नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व पर कथित लगातार हमलों और देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ लोगों द्वारा मुस्लिमों की आस्था पर कथित हमलों से संबंधित घृणा अपराध के मामले में अदालत की निगरानी में जांच और अभियोजन का अनुरोध किया गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के माध्यम से दाखिल याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि नफरत वाले भाषणों, विशेष रूप से पैगंबर मोहम्मद की शख्सियत को निशाना बनाकर दिए गए बयानों के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई कार्वाई पर रिपोर्ट दी जाए।

अधिवक्ता एम आर शमशाद द्वारा दाखिल याचिका में देशभर में घृणा भाषणों से संबंधित अपराधों के सिलसिले में की गई समस्त शिकायतों को एक साथ शामिल करके स्वतंत्र जांच समिति गठित करने का निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया, पैगंबर मोहम्मद का अपमान इस्लाम की पूरी बुनियाद पर ही हमला करने के समान है और इस तरह यह अत्यंत गंभीर प्रकृति का है क्योंकि इसके नतीजतन न केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों पर निशाना साधा जाता है, बल्कि उनकी आस्था की बुनियाद पर भी हमला किया जाता है। इसमें कहा गया कि ऐसे भाषण किसी अन्य की आस्था की आलोचना की स्वीकार्य सीमा से परे जाकर दिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से धार्मिक असहिष्णुता को भड़का सकते हैं। याचिका के अनुसार राज्य और केंद्र के अधिकारियों को इन्हें विचारों तथा धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के संदर्भ में असंगत मानना चाहिए और समुचित प्रतिबंधात्मक कदम उठाने चाहिए। संगठन ने कहा कि उसने काफी समय तक इंतजार करने और शासकीय अधिकारियों को उचित कदम उठाने के लिए पर्याप्त वक्त देने के बाद यह याचिका दायर की है। हाल में 76 वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि दिल्ली और हरिद्वार में आयोजित अलग-अलग समारोहों में कथित रूप से दिए गए नफरत भरे भाषणों का स्वतः संज्ञान लिया जाए। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि आयोजनों में दिए गए भाषण न केवल नफरत भरे थे, बल्कि एक पूरे समुदाय की हत्या का खुला आह्वान भी थे। पत्र के अनुसार, ये भाषण न केवल हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा हैं, बल्कि लाखों मुस्लिम नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।

पाकिस्तान में घरेलू गैस की किल्लत से हाहाकार, खाना बनाने तक के लिए संघर्ष कर रहे लोग

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में घरेलू गैस की किल्लत से हाहाकार मची हुई है। लोगों को खाना बनाने तक के लिए गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है । टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन (टीआरटी) के अनुसार पाकिस्तान में गैस की कमी के चलते लोगों को खाना बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गैस किल्लत की मौजूदा स्थिति को

देखते हुए पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की । प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि 'पीएम @ImranKhanPTI ने पाकिस्तान में गैस की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में घरेलू भंडार से मांग और आपूर्ति, प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की कमी और आयात के बारे में जानकारी दी गई।' रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में इमरान खान ने अधिकारियों को घरेलू अन्वेषण के लिए लाइसेंस फास्ट-ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसे प्राकृतिक गैस का सबसे सस्ता स्रोत बताया है। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों से नए एलएनजी प्लांट और वर्चुअल पाइपलाइन परियोजनाओं की प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं।

नवाज के लौटने की खबर पर पाक गृह मंत्री ने फिर कसा तंज, बोले- उनके लिए ऑफर आज भी

इस्लामाबाद: पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संभावित वापसी की अफवाहों के बीच, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा कि शरीफ के लौटने की बातें बेमतलब की हैं जो विपक्ष मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहा है। रावलपिंडी में रशीद ने मीडिया से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि शरीफ के लिए पाकिस्तान लौटने का एक तरफ का टिकट देने का उनका प्रस्ताव आज भी है। एक अदालत ने शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा सुनाई थी जिसके बाद लाहौर उच्च न्यायालय ने 2019 में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर चार सप्ताह के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी। हालांकि, लंदन जाने के बाद से शरीफ पाकिस्तान नहीं लौटे हैं। उनकी पार्टी का कहना है की डॉक्टरों द्वारा सलाह देने पर 71 वर्षीय शरीफ देश वापस लौटेंगे। गृह मंत्री ने कहा, 'शरीफ के वापस आने को बेवजह तूल दिया जा रहा है।' उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों ने अपनी ज्यादातर जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी वह देश को प्यार करने की बजाय उसे छोड़कर चले गए।

पाकिस्तान के वजीरिस्तान में विस्फोटों में 3 सुरक्षाकर्मियों सहित 5 की मौत, 2 घायल

पेशावर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए दो विस्फोटों में तीन सुरक्षाकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। खबर के मुताबिक धमाका उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मिराली तहसील के मामाखेल क्षेत्र में एक ट्यूबवेल के पास अज्ञात बदमाशों ने विस्फोटक रखा था। आईईडी में धमाके के साथ विस्फोट हुआ जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। दो अन्य घायलों को बन्नू जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के अली तहसील में हुए एक विस्फोट में तीन सुरक्षाकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा बलों के एक काफिले पर रिमोट नियंत्रित विस्फोट से हमला किया गया, जिसमें तीन सैनिक और एक नागरिक घायल हो गया। पता चला है कि संदिग्ध आतंकवादियों ने सड़क के किनारे विस्फोटक उपकरण रखा था, जो इलाके से गुजरने वाले सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने वाला था।

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत तिरुमूर्ति बोले-

पीएम ने पहली बार UNSC में बैठक की अध्यक्षता की, यह भारत के लिए गर्व की बात

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब तक भारत की मौजूदगी का मुख्य आकर्षण अगस्त में अध्यक्षता करने की रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार हस्ष्ट की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह भारत और भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। इसके अलावा तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान पर संकल्प 2593 को हमारी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था। यह संकल्प पर इस बात का समर्थन करता है कि अफगानिस्तान की धरती का

इस्तेमाल अन्य देशों के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा और काबुल के अधिकारी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे।

पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि फिलिस्तीनी और इजराइल की सुरक्षा की चिंताओं को केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है।

रक्षा सौदा: पाकिस्तान ने चीन से खरीदे 25 जे-10सी लड़ाकू विमान, हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम

संयुक्त राष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान अब अपनी सेना को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के खरीदे जाने के बाद अब पाकिस्तान ने भी चीन से 25 जे-10सी लड़ाकू विमान खरीदे हैं जो हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम हैं।

चीन के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में से एक

पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने बुधवार को यह जानकारी दी कि जे-10सी के 25 विमानों का एक पूरा बेड़ा अगले साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। जे-10सी को चीन के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है।

पाकिस्तान के पास अमेरिका के एफ-16 लड़ाकू विमान

पाकिस्तान के पास पहले से ही अमेरिका में बने एफ-16 श्रेणी के लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा मौजूद है। वहीं चीन अपने बेहद विश्वसनीय लड़ाकू विमानों में से एक जे-10सी को पाकिस्तान को देने के बाद एक बड़ा सहयोगी बन गया है।

चीन के 25 जे-10सी लड़ाकू विमान भारत के राफेल का जवाब

गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार 23 मार्च के समारोह में

शामिल होने के लिए वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। जे-10सी का फ्लाई पास्ट समारोह आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान वायुसेना चीन के जेएस का फ्लाई-पास्ट करने जा रही है। उनहोंने कहा कि चीन के 25 जे-10सी लड़ाकू विमान भारत के राफेल का जवाब हैं।

पाबंदी: पाकिस्तानी विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के जींस-टीशर्ट पहनने पर प्रतिबंध

लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय फैसलाबाद छात्र-छात्राओं के पहनावे व रहन-सहन पर पाबंदियां लगाई हैं। टोबा टेक सिंह स्थित सब-कैंपस में लड़कों को स्किनफिट मल्टी पॉकेट, फेडेड या कटी-फटी जींस, ट्राउजर के चप्पल और संदेश लिखें टी-शर्ट पहने से रोक दिया। वे पोनी टेल व लंबे बाल भी नहीं रखेंगे। लड़कियों को इन पाबंदियों के साथ बालियां, स्लीपर, ब्रेसलेट आदि न पहनने के लिए कहा है।

कुछ माह पहले भी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (एफबीई) ने इसी प्रकार के प्रतिबंधों की घोषणा की थी। आदेश में कहा कि लड़कियां जींस के साथ स्लीक्लैस टीशर्ट व शर्ट, हल्की पारदर्शिता वाले या स्किन टाइट परिधान, चमकदार आभूषण, पायल न पहनें। उन्हें हैवी मेकअप भी नहीं करने के लिए कहा

है। शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण करने वाले एफडीई ने इससे पहले दिए आदेश में शिक्षिकाओं से कहा था कि वे जींस व टाइट कपड़े न पहनें। पुरुषों को जींस, टीशर्ट से रोका था। बाल कटवाने, दाढ़ी ट्रिम करने, नाखून काटने जैसे निर्देश भी दिए थे। विश्वविद्यालय से पहले खैबर पख्तूनख्वा के दो विश्वविद्यालय ने भी सख्त ड्रेस कोड लागू किया था।

पंजाब के टोबा टेक सिंह स्थित कृषि विद्यालय में विद्यार्थियों के पहनावे व रहन-सहन पर बंदिशें

लड़के : मल्टी पॉकेट फेडेड या फटी जींस व ट्राउजर, कैप, चप्पल व संदेश लिखे टी-शर्ट पहनने से रोका।

लड़कियां: जींस, स्लीवलैस टीशर्ट, शर्ट हल्के पारदर्शी स्किन टाइट परिधान, चमकदार आभूषण, बालियां, ब्रेसलेट, पायल, मेकअप भी प्रतिबंधित।

पाकिस्तान में बिजली गैस के लिए प्रदर्शन

बिजली और गैस की कटौती से जूझ रहे पाकिस्तान के लक्की शहर में बड़ी संख्या में नकाबपोश महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया दर्शन के अनुसार महिलाओं ने बन्नू से मियांवाली जोड़ने वाली सड़क पर जाम लगा दिया। बिजली और गैस की किल्लत के नारे लिखी तख्तियां थी। महिलाओं ने बताया बिजली की समस्या बढ़ा दी हैं।

किसानों का खाद के लिए विरोध प्रदर्शन

द डॉन की खबर के अनुसार, खाद विक्रेताओं की हड़ताल से यूरिया न मिलने से परेशान पीरमहल के किसानों प्रदर्शन करते हुए फैसलाबाद मुल्तान हाईवे और रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा दिया इससे हाइवे पर 1 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा। किसानों ने कहा कि सरकारी मूल्य पर खाद भेजना भरोसा दिलाया गया था लेकिन घंटों बाद भी नहीं मिली। किसानों ने खाद की तहत कीमत पर उपलब्ध कराने का आश्वासन के बाद धरना खत्म किया।

लोकतंत्र समर्थकों पर चीन की कार्रवाई, 'स्टैंड न्यूज' वेबसाइट बंद, 7 मीडियाकर्मी गिरफ्तार

हांगकांग। लोकतंत्र समर्थकों पर चीन की दमनात्मक कार्रवाई जारी है। ताजा मामले में लोकतंत्र समर्थित 'स्टैंड न्यूज' नामक वेबसाइट के कार्यालय पर छापेमारी के बाद उसे बंद कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि स्टैंड न्यूज एक पूर्व संपादक तथा एक मौजूदा संपादक समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें चार महिलाएं भी हैं। साथ ही संस्थान से जुड़ी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार उनके आवासों पर भी तलाशी ली जा रही है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में मुख्य संपादक चुंग पुई-कुएन और पैट्रिक लैम, गायक एवं कार्यकर्ता डेनिस हो और पूर्व सांसद मार्गरेट न्गो भी शामिल हैं।

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई 'राजद्रोह और उकसावे' संबंधी सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में की गई है। पुलिस के मुख्य सचिव जॉन ली ने बुधवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पत्रकारिता को हथियार बनाकर सुरक्षा के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता।

उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यवहार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति लागू होगी। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान करीब 200 से अधिक पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसके उप संपादक, रॉनसन चैन के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। डेनिस हो दरअसल बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं। बोर्ड के अन्य सदस्य मार्गरेट एनजी, क्रिस्टीन फांग और चाउ टाट-ची को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई से पहले 'स्टैंड न्यूज' ने अपने फेसबुक पेज पर एक लाइव प्रसारण किया। इसमें बताया कि पुलिस डिप्टी असाइनमेंट संपादक रॉनसन चैन के घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी है। इस वीडियो में अधिकारी यह

कहते देखे गए कि उनके पास घर की तलाशी का वारंट है। चर्चित एपल डेली के बाद स्टैंड न्यूज हांगकांग की दूसरी ऐसी लोकतंत्र समर्थित मीडिया कंपनी है जिसे निशाना बनाया गया है। इसी साल जून में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एपल डेली की संपत्ति को फ्री कर दिया गया था। इसके बाग इसे बंद करना पड़ा।

आईएसआई के नए प्रमुख का अधिकारियों को निर्देश, मीडिया में न जारी करें मेरी तस्वीरें-वीडियो रिकॉर्डिंग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के नवनियुक्त अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पाकिस्तानी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया में जारी न करें।

यह जानकारी बुधवार को एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में दी गई। देश के नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच लंबे गतिरोध के बाद पिछले महीने अंजुम को आईएसआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

अंजुम ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह ली है। इस साल अगस्त में तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में तख्तापलट करने के दौरान फैज हमीद का एक वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो में वह काबुल में एक रिपोर्टर से बात करते नजर आए थे। अंजुम के इस निर्देश को लेकर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के पूर्व अधिकारियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और उनके इस फैसले के प्रति समर्थन व्यक्त किया है।

हुई बैठक की तस्वीरों में नहीं दिखे थे आईएसआई प्रमुख

वहीं, एक उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने देश की पहली राष्ट्रीय

सुरक्षा नीति को अनुमति दी थी। इस बैठक में आईएसआई के महानिदेशक भी शामिल हुए थे। न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने इस बैठक की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की थीं। इन तस्वीरों में सभी शीर्ष पदाधिकारियों को देखा जा सकता है लेकिन आईएसआई के प्रमुख इनमें कहीं नहीं दिखे। रिपोर्ट के अनुसार एक मंत्री ने बताया है कि आईएसआई प्रमुख ने सरकारी अधिकारियों को अपनी तस्वीरें और वीडियो फुटेज मीडिया में न जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने कहा कि खुफिया सेवाओं का मूल सिद्धांत यही है कि मीडिया से दूर रहे और गुमनामी बरकरार रखे। हालांकि, उन्होंने कहा कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें सरकारी अधिकारियों ने इस सिद्धांत का उल्लंघन किया है। इसके अलावा पूर्व में आईएसआई में सेवा दे चुके सेवानिवृत्त मेजर जनरल एजाज अवान ने इसे लेकर कहा कि आईएसआई के नए प्रमुख मीडिया की सुर्खियों में आए बिना काम करने का तरीका जारी रखना चाहते हैं।

जलवायु परिवर्तन का असर: अमेरिका के जंगलों की आग से लेकर भारत में भीषण बाढ़ तक, 2021 में हर महीने दिखीं बड़ी आपदाएं

वॉशिंगटन/बीजिंग। साल 2021 खत्म होने की कगार पर है। कोरोनावायरस महामारी की वजह से 2021 को 2020 से भी खतरनाक करार दिया जाता है। इस वैश्विक महामारी को मानव इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में भी गिना जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि, कुछ और आपदाओं ने भी लोगों की समस्याओं को बढ़ाने का काम किया। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो, जहां जलवायु परिवर्तन के असर से कोई भयानक आपदा न आई हो।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तेजी से दुनियाभर में जलवायु परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस लिहाज से आने वाले साल में धरती को और बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पिछले 20 सालों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सामने आता है कि इस दौरान कुल 7438 आपदाएं रिकॉर्ड की गईं। इनमें करीब 12 लाख से ज्यादा जानें चली गईं। अकेले चीन में ही 577 आपदाएं आईं, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका का नाम है, जहां 467 आपदाएं रिकॉर्ड की गईं। भारत में पिछले 20 सालों में 321 आपदाएं दर्ज हुई हैं।

साल भर में क्या हुईं बड़ी घटनाएं?

पृथ्वी के इसी बिगड़ते हालात से आगाह करने के लिए अमर उजाला आपको 2021 के हर महीने में जलवायु परिवर्तन की वजह से आई बड़ी आपदाओं के बारे में बता रहा है।

फरवरी- अमेरिका के सबसे गर्म राज्यों में से एक टेक्सास में जबरदस्त शीतलहर रिकॉर्ड हुई। इसमें 125 लोगों की मौत हुई। जबरदस्त ठंड के बीच लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने को मजबूर होना पड़ा। वैज्ञानिकों को शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर टेक्सास में मौसम अचानक क्यों बदला। हालांकि, अब यह सामने आया है कि आर्कटिक में गर्मी बढ़ने की वजह से दुनियाभर में मौसम पर अजीब प्रभाव पड़ रहा है।

मार्च: चीन की राजधानी बीजिंग में अचानक ही धूलभरे गुबार में सबकुछ ढक गया। आलम यह था कि यहां से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को तुरंत रोकना पड़ा। वैज्ञानिकों ने इसे पूरे दशक की सबसे खराब आंधी करार दिया था।

अप्रैल: असम में 28 अप्रैल 2021 को 6.4 तीव्रता के भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई। इस प्राकृति आपदा की वजह से दो मौतें हुईं, जबकि 12-13 लोग

गंभीर रूप से घायल भी हुए।

मई: भारत के लिए ये महीना काफी चुनौतीभरा रहा। इस महीने देश को दो-दो चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ा। पहला चक्रवाती तूफान %ताउते% 14 मई 2020 को अरब सागर में आया था और इससे गुजरात बुरी तरह प्रभावित हुआ। ताउते की वजह से करीब 174 लोगों की जान गई, जबकि 80 लोग अब तक लापता हैं। इसके अलावा दो लाख लोगों को अपने घर छोड़कर कैंपों में रहना पड़ा।

दूसरा चक्रवाती तूफान 'यास' रहा, जिसने पश्चिम बंगाल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 23 मई 2021 को यास ओडिशा से टकराया और बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश पहुंच गया। दोनों देशों में इसकी वजह से करीब 20 लोगों की मौत हुई।

जून: अमेरिका और कनाडा में यह साल भयानक गर्मी का रहा। इस दौरान दोनों देशों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक गया। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को अहम वजह करार दिया था। भीषण गर्मी की वजह से दोनों देशों में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। इतना ही नहीं अमेरिका में तो बिजली के तार तक गल गए थे और सड़कें टूटने लगीं। कई शहरों में इस दौरान कूलिंग सेंटर्स खोले गए, जहां लोगों को गर्मी से बचाने के इंतजाम किए गए थे।

इसी महीने अमेरिका भीषण सूखे का भी सामना कर रहा था। 2020 की शुरुआत में पानी की कमी से पैदा हुई स्थिति जून की भीषण गर्मी में और गंभीर हो गई। किसानों ने बचाव के लिए अपनी फसलों को छोड़ दिया। अधिकारियों ने भी हूवर बांध में पानी के रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाने की वजह से आपातकाल का एलान कर दिया था।

जुलाई: 2021 का यह महीना भी दुनिया के लिए भारी साबित हुआ। भारत के महाराष्ट्र में बारिश का सीजन कई चुनौतियां लेकर आया। 22 जुलाई को राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे शहरों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं कुछ और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ भी देखी गई। महाराष्ट्र में इस आपदा में 251 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 लोग लापता थे। गोवा में भी जबरदस्त बारिश की वजह से दशकों में सबसे खराब बाढ़ रिकॉर्ड हुई।

उधर चीन के हेनान प्रांत में भी जबरदस्त बारिश और उसके चलते आई बाढ़ में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चीन के मौसम विबाग के मुताबिक, जुलाई के तीन दिनों में ही इतनी बारिश हुई, जितनी एक साल में होती है। इसका असर यह हुआ कि मेट्रो में सफर कर रहे यात्री भी पानी के बीच फंसे नजर आए।

इसके अलावा यूरोप के जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में जबरदस्त बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी रही। इन तीन देशों में 200 से ज्यादा की मौत हुई। वैज्ञानिकों का कहना था कि जलवायु परिवर्तन के चलते आने वाले समय में ऐसी घटनाओं के 20 फीसदी तक ज्यादा होने के आसार हैं।

जहां आधी दुनिया जुलाई में बारिश से प्रभावित थी, वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया और ओरेगॉन के जंगलों में लगीं दो बड़ी आग इन राज्यों के इतिहास की सबसे बड़ी वाइल्डफायर साबित हुईं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने इस दौरान ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते दशकों लंबे सूखे का एक और साल देखा। ब्राजील के लिए भी यह साल सदी के सबसे सूखे वर्षों में रहे हैं

अगस्त: इस महीने मेडिटेरेनियम के तीन देश अल्जीरिया, ग्रीस और तुर्की जंगलों में लगी आग से जूझते दिखे। जहां ग्रीस में दो लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अल्जीरिया में 65 की जान गई। उधर अगस्त के अंत तक एल्प्स की पहाड़ियों पर जमी बर्फ गर्म होते तापमान की वजह से पिघलना शुरू हो गई। बर्फ को बचाने के लिए स्विट्जरलैंड के रिसॉर्ट कर्मचारियों को माउंट टिटलिस पर कंबल तक डालते देखा गया था।

सितंबर: भारत के लिए ये चक्रवाती तूफान से जूझने का एक और महीना रहा। बंगाल की खाड़ी में उठा 'गुलाब' चक्रवात 24 सितंबर को रफ्तार पकड़ने के बाद 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश से टकराया था। हालांकि, इसके बाद यह कमजोर पड़ता चला गया। सुरक्षा कारणों से करीब 56 हजार लोगों को कैंपों में ले जाया गया था।

भारत के अलावा अमेरिका में भी चक्रवाती तूफान ईडा ने तबाही मचाई। यह लूजियाना से टकराने के दौरान कैटेगरी 4 का तूफान था। इसकी चपेट में आकर लूजियाना में ही 100 लोगों की मौत हुई थी। आगे बढ़ने के बाद कई और जानें गईं। साथ ही पूरे देश में जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति भी पैदा हुई।

नवंबर: भारत में नवंबर की शुरुआत ही एक आपदा के साथ हुई। एक नवंबर को तमिलनाडु में शुरू हुई जबरदस्त बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया। इसमें 41 लोगों की जान चली गई और 11 हजार लोग विस्थापित हो गए।

इसी दौरान दक्षिणी सूडान में 60 साल में सबसे खतरनाक बाढ़ देखी गई। इससे 7 लाख 80 हजार लोग प्रभावित हुए। यानी हर 14 में से एक नागरिक। जलवायु परिवर्तन की वजह से दक्षिणी सूडान में भारी बारिश लगातार तीन सालों से बाढ़ का रूप ले रही है। इसके अलावा कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भी नवंबर में जबरदस्त बारिश ने तबाही मचाई। यह कनाडा के पूरे इतिहास में सबसे महंगी प्राकृतिक आपदा रही।

फिर कांपी धरती- इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके हुए महसूस, रिक्टर स्केल पर 7. 3 रही तीव्रता

इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। देश के तिमोर-लेस्ते प्रांत से करीब 113 किमी उत्तर पूर्व में कबुपाटेन मालुकु बरत दया में अत्यंत शक्तिशाली

भूकंप के झटके महसूस किए गए।भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई है। तेज भूकंप आने से लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। प्रशासन ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि, अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। यूरोपीय-भूमध्य भूकंपीय केंद्र (ईएमएससी) के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार तड़के 3.25 बजे आया। बता दें कि इंडोनेशिया में आए दिन भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।

दिल्ली देहात के किसान पालम-360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में हुक्का पानी लेकर पहुँचे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के आवास

नई दिल्ली। दिल्लीके सीएम और उपराज्यपाल आवास के बाहर दिल्ली देहात के किसान, पालम-360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में अपना हुक्का पानी लेकर पंचायत करने पहुंच गए। उनकी मुख्य मांग ये है कि नई आबकारी नीति के तहत गांव देहात में शराब के नए ठेके खोले जाने के निर्णय को तुरंत निरस्त किया जाए और वर्षो से लंबित दिल्ली देहात के सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान किया जाए।

दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल आवास के बाहर दिल्ली देहात के लोग पालम-360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में महापंचायत करने पहुंचे किसानों और ग्रामीणों की ये पंचायत मुख्यतः नई आबकारी नीति के तहत गांव देहात में खोले जा रहे हैं नए शराब के ठेकों के विरोध में बुलाई गई है। जबकि दिल्ली में बंद म्यूटेशन प्रक्रिया को पूर्ण बहाल करने, अन्य राज्यों की तुलना में जमीन अधिग्रहण पर कम मुआवजा की राशि को उचित सीमा तक बढ़ाये जाने और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों का डीडीए द्वारा अधिग्रहण किए जाने पर रोक लगाने जैसी मांगे भी जुड़ी हैं।

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को कई बार पत्र लिखकर मांग रखा कि दिल्ली देहात में नई आबकारी नीति के तहत शराब के नए ठेके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही हमने कई बार दिल्ली देहात के मुद्दों को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर भी उनके सामने रखा है लेकिन आश्वासन के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिला है। इसलिए आज हम सीएम और उपराज्यपाल आवास के बाहर दिल्ली देहात की मांगों को लेकर अपनी पंचायत कर रहे हैं। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी कीमत पर गांव देहात के मुद्दों की अनदेखी नहीं होने देंगे और ना ही हम अपने गांव में शराब के ठेके खुलने देंगे क्योंकि इससे हमारे सामाजिक व्यवस्था ख़राब होने का ख़तरा है।

इस पंचायत में मुख्यतः चौधरी नरेश प्रधान लाडो सराय 96, चौधरी धारा सिंह प्रधान बवाना बावनी, चौधरी अजय नंबरदार प्रधान तिहाड़ 28, चौधरी दिलीप मान प्रधान लोवा 17, चौधरी नारायण सिंह, चौधरी रणबीर प्रधान नरेला 17, चौधरी समुंदर सिंह प्रधान कराला 17 और चौधरी नारायण सिंह प्रधान ढांसा 12 सिंह सहित कई गणमान्य लोग और ग्रामीण लोग शामिल रहे।दिल्ली देहात के किसान पालम-360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में हुक्का पानी लेकर पहुँचे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के आवास

दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल आवास के बाहर दिल्ली देहात के किसान, पालम-360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में अपना हुक्का पानी लेकर पंचायत करने पहुंच गए। उनकी मुख्य मांग ये है कि नई आबकारी नीति के तहत गांव देहात में शराब के नए ठेके खोले जाने के निर्णय को तुरंत निरस्त किया जाए और वर्षो से लंबित दिल्ली देहात के सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान किया जाए।

दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल आवास के बाहर दिल्ली देहात के लोग पालम-360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में महापंचायत करने पहुंचे किसानों और ग्रामीणों की ये पंचायत मुख्यतः नई आबकारी नीति के तहत गांव देहात में खोले जा रहे हैं नए शराब के ठेकों के विरोध में बुलाई गई है। जबकि दिल्ली में बंद म्यूटेशन प्रक्रिया को पूर्ण बहाल करने, अन्य राज्यों की तुलना में जमीन अधिग्रहण पर कम मुआवजा की राशि को उचित सीमा तक बढ़ाये जाने और ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों का डीडीए द्वारा अधिग्रहण किए जाने पर रोक लगाने जैसी मांगे भी जुड़ी हैं।

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को कई बार पत्र लिखकर मांग रखा कि दिल्ली देहात में नई आबकारी नीति के तहत शराब के नए ठेके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही हमने कई बार दिल्ली देहात के मुद्दों को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर भी उनके सामने रखा है लेकिन आश्वासन के बावजूद भी कोई समाधान नहीं मिला है। इसलिए आज हम सीएम और उपराज्यपाल आवास के बाहर दिल्ली देहात की मांगों को लेकर अपनी पंचायत कर रहे हैं। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी कीमत पर गांव देहात के मुद्दों की अनदेखी नहीं होने देंगे और ना ही हम अपने गांव में शराब के ठेके खुलने देंगे क्योंकि इससे हमारे सामाजिक व्यवस्था ख़राब होने का ख़तरा है।

आज की इस पंचायत में मुख्यतः चौधरी नरेश प्रधान लाडो सराय 96, चौधरी धारा सिंह प्रधान बवाना बावनी, चौधरी अजय नंबरदार प्रधान तिहाड़ 28, चौधरी दिलीप मान प्रधान लोवा 17, चौधरी नारायण सिंह, चौधरी रणबीर प्रधान नरेला 17, चौधरी समुंदर सिंह प्रधान कराला 17 और चौधरी नारायण सिंह प्रधान ढांसा 12 सिंह सहित कई गणमान्य लोग और ग्रामीण लोग शामिल रहे।

समय से पहले हुनर हाट का समापन, आज दोपहर तक चलेगा मेला

■ नई दिल्ली

पहले तय शेड्यूल के मुताबिक 5 जनवरी तक होना था हुनर हाट का आयोजन

दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 35वें हुनर हाट का समापन शुक्रवार को दोपहर बाद होगा। मेले की समापन की घोषणा केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरूवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जेएलएन स्टेडियम में आयोजित हुनर हाट में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार कारीगर शामिल हुए। ये कलाकार अपने साथ हस्तनिर्मित शानदार एवं दुर्लभ स्वदेशी उत्पाद लेकर आए।

वही हुनर हाट के बावर्चीखाना में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारम्परिक पकवानों ने हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के जायके का मजा दिया। नकवी ने कहा कि हुनर हाट में आने वाले लोगों ने विश्वकर्मा वाटिका, पारम्परिक सर्कस देश के जाने-माने कलाकारों के विभिन्न सांस्कृतिक,गीत,संगीत के कार्यक्रमों का आनंद भी लिया। नकवी ने कहा कि लोगों ने बड़े पैमाने पर दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के स्वदेशी उत्पादनों की खरीददारी कर उनकी हौसला अफजाई की।

लोक कल्याण की भावना से हल हो सकते हैं कठिन सामाजिक मुद्दे : सुमित

नई दिल्ली। गिवइंडिया के वार्षिक गिविंग सर्वे के अनुसार भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन 85 प्रतिशत रेस्पोंडेंट्स का मानना है कि इस तरह के कठिन सामाजिक मुद्दों का समाधान में लोक कल्याण की भावना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गिवइंडिया के सीओओ सुमित तयाल ने कहा हमारे इस गिविंग बेहेवियर के वार्षिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नागरिक भारत की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं, जिसको कि कोविड ने अत्याधिक वास्तविक और जरूरी बना दिया है। इसके साथ ही महामारी ने परोपकार और साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। जिसमें कि एक ही लक्ष्य की दिशा में एक साथ काम करने वाली संस्थाओं पर अधिक असर पड़ा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में प्राथमिकी रद्द करने से किया इनकार

एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति और उसकी मृत पत्नी के परिवार के बीच एक समझौते के आधार पर दहेज हत्या की प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है जो एक सामाजिक बुराई से प्रेरित है और इसे रोकने की जरूरत है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए व्यक्ति और आरोपी परिवार के अन्य सदस्यों की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दहेज हत्या का अपराध समाज के खिलाफ अपराध है। पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला सुनाया है कि किसी समझौते के आधार पर गंभीर मामलों को बंद नहीं किया जा सकता है। अदालत ने हालिया आदेश में कहा, वर्तमान मामले में एक महिला ने पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण शादी के पांच महीने के भीतर आत्महत्या कर ली और भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत दंडनीय अपराध न केवल एक गंभीर और जघन्य अपराध है बल्कि दहेज की मांग सामाजिक बुराई से प्रेरित समाज के खिलाफ अपराध है। इस प्रकार के अपराध को रोकने की आवश्यकता है। इसलिए, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। मौजूदा मामले में महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि मार्च 2021 में शादी के बाद से याचिकाकर्ता उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद अगस्त में परिवार को फोन आया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जांच लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं और महिला के परिवार ने एक समझौता किया, जिसमें कहा गया था कि वे बिना किसी जबरदस्ती और बिना किसी पैसे के हस्तांतरण के एक समझौता कर चुके हैं। समझौते में महिला के परिवार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनका कोई दावा और शिकायत नहीं है और याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हुए याचिका खारिज कराने में सहयोग करेंगे।

समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन

■ नई दिल्ली

स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि, कंप्यूटेशनल व डिजाइन थिंकिंग समेत कोडिंग के कौशल का विकास करने के उद्देश्य से आयोजित एडब्लूएस यंग बिल्डर्स चैलेंज 2021 में दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल के 10 स्कूल विजेता बनकर उभरे। स्मार्ट फार्मिंग और स्मार्ट इरीगेशन, शहरी परिवहन प्रबंधन और यूटिलिटीज मैनेजमेंट में वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए स्कूली विद्यार्थियों ने बेहतरीन समाधानों का प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्रालय इनोवेशन सेल (भारत सरकार), अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई), और कोड ओआरजी के सहयोग से लॉन्च किए गए इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को क्लाड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग (एमएल) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आदि के मूलभूत तत्वों का परिचय देना और उन्हें इन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करना है। सुनील पीपी, लीड एजुकेशन, स्पेस एंड नॉन-प्रॉफिट्स, एडब्लूएस इंडिया व साउथ एशिया, एमेजॉन इंटरनेट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल इनोवेशन व ट्रांसफॉर्मेशन का केंद्र है, और एडब्लूएस में हमारा यकीन है कि मशीन लर्निंग हमारी पीढ़ी की सबसे परिवर्तनकारी तकनीक बनेगी।

कपड़ों पर प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि के खिलाफ दिल्ली में कपड़ा कारोबारियों ने दुकानें बंद रखीं

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर एक जनवरी से जीएसटी दर मौजूदा पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के प्रस्तावित कदम के विरोध में दिल्ली में कपड़ा कारोबार से जुड़े कई बाजार बृहस्पतिवार को बंद रहे। हड़ताल के आह्वान के बाद चांदनी चौक, गांधी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, ओखला, शांति मोहल्ला, पीतमपुरा, जोगीवाड़ा, रोहिणी के 64 छोटे और मध्यम बाजारों समेत कई अन्य बाजार भी बंद रहे।

दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भगवान बंसल ने कहा कि कपड़े और रेडीमेड कपड़ों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी से व्यवसाय खत्म हो जाएगा और आम आदमी की जेब पर भी बड़ा बोझ पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण कपड़े पहले ही लगभग 30 प्रतिशत महंगे हो गए हैं और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से कारोबार पर और असर पड़ेगा।

बंसल ने पीटीआई-भाषा से कहा, हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह निर्णय वापस ले और इस पर व्यापारियों के साथ बातचीत करे। अगर यह मांग नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इस संबंध में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने व्यापारियों की हड़ताल का समर्थन किया और कहा कि वह शुक्रवार की जीएसटी परिषद की बैठक में हम व्यापारियों की मांग रखेंगे।

इस संबंध में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, कपड़ा व्यापारी जीएसटी की दरें पांच प्रतिशत से12 प्रतिशत किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी यह मांग जायज है।अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार हमेशा कर दरों को कम रखने के पक्ष में रही है। कल होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में मैं कपड़ों पर कर कम रखने की मांग रखूंगा।

पति पत्नी के विवाद में बच्चे को कठिनाई नहीं होना चाहिए : कोर्ट

एजेंसी ■ नई दिल्ली

वैवाहिक रिश्तों में कटुता उत्पन्न होने से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि माता पिता के बीच विवाद के कारण बच्चे को कठिनाईं नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सेना के एक अधिकारी को उसके 13 साल के बेटे के वयस्क होने तक उसकी देखभाल और भरण-पोषण करने का निर्देश दिया। सैन्य अधिकारी का विवाह विच्छेद करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अधिकारी को अपनी पत्नी को 50 हजार रुपए बतौर भरण-पोषण भत्ता देने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पति और पत्नी दोनों मई 2011 से साथ में नहीं रह रहे हैं , इसलिए, यह कहा जा सकता है कि उनके बीच विवाह टूट चुका है जिसमें सुधार नहीं हो सकता है। पीठ ने कहा, यह भी बताया गया है कि पति ने पहले ही दूसरी शादी कर ली है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके परिवार अदालत द्वारा पारित डिक्री में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा, हालांकि, साथ ही, पति को बेटे को वयस्क होने तक उसके दायित्व और जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। पति-पत्नी के बीच चाहे जो भी विवाद हो, संतान को इससे कठिनाईं नहीं होना चाहिए। पीठ ने कहा, बच्चे:बेटे के वयस्क होने तक उसका दायित्व उसके पिता की जिम्मेदारी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि (इस मामले में) मां कुछ भी नहीं कमा रही है और इसलिए, बेटे की शिक्षा आदि सहित उसके भरण-पोषण के लिए उचितापर्याप्त राशि की आवश्यकता है, जिसका भुगतान पति को करना होगा। अदालत ने कहा, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, अपीलकर्ता-पत्नी और पति के बीच विवाह के विघटन के डिक्री की पुष्टि करके वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है। पीठ ने अपने हालिया फैसले में कहा, इसलिए पति को दिसंबर 2019 से बेटे के भरण पोषण के लिए हर महीने 50 हजार रुपए पत्नी को देने का आदेश दिया जाता है। दोनों का विवाह 16 नवंबर 2005 को हुआ था। पत्नी ने सैन्य अधिकारियों के समक्ष पति के खिलाफ कई शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें विवाहेत्तर संबंध की शिकायत भी है। अधिकारियों ने उस अधिकारी के खिलाफ एक जांच शुरू की थी।

जेएनयू में ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियां और डॉ बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी रहेंगी बंद

■ नई दिल्ली

दिल्ली में कोरोना का संक्रमण के चलते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन के द्वारा एक ऑर्डर जारी कर अगले आदेश तक ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियां और डॉ बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी बंद रखने का ऐलान किया है।

जेएनयू प्रशासन द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि बढ़ते नाइट कर्फ्यू के दौरान विश्वविद्यालय में केवल इमरजेंसी सेवा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी जाने वाले व्यक्ति को ही आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, वॉटर प्यूरीफायर रिपेयर करने वाले व्यक्ति को भी वैलिड आई कार्ड दिखाने के बाद आने जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कहा कि खाद्य पदार्थ, दूध की दुकान, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, पोस्टल सर्विस आदि जिन सेवाओं को डीडीएमए के द्वारा छूट दी गई है।

इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरकार के द्वारा जारी किए गए कोविड.19 नियमों का सभी को सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदर्शन *दिल्ली महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बृहस्पतिवार को राजधानी में बलात्कार की घटना के विरोध में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए।*

लेखा-जोखा *5जी तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला के मुकदमे को खारिज कर दिया*

2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिए महत्वपूर्ण आदेश

एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2021 में कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान चिकित्सकीय ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड की कमी जैसे मुद्दों के लिए प्राधिकारों के रुख पर अप्रसन्नता जताई और नेताओं से संबंधित मामलों में आदेश पारित करके नागरिकों के दुखों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया कंपनियों और विरोध करने के अधिकार पर भी महत्वपूर्ण आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने कोविड-19 रोगियों को अस्पताल के बिस्तर और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह भी चेतावनी दी राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालने की कोशिश करने वालों को लटका देगा। लोकतंत्र में असहमति की भूमिका उजागर करने वाले ऐतिहासिक फैसले में 2020 के दंगों में कुछ छात्र प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों से संबंधित मामलों ने भी फेसबुक और वाट्सऐप के साथ वर्ष के दौरान उच्च न्यायालय को व्यस्त रखा, विशेष रूप से उन दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई, जिनमें चैट (संवाद) का पता लगाने की आवश्यकता थी। केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या तो खुद या अधिकारियों की सहायता करके अवैध सामग्री का मुकाबला करने की उम्मीद है और नियमों से प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों को फर्जी खबरों से बचाने में मदद मिलेगी। उच्च न्यायालय ने 5जी तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला के मुकदमे को खारिज कर दिया और याचिका को दोषपूर्ण, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और प्रचार हासिल करने के लिए दायर बताते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी सहित कुछ अन्य नेताओं ने भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज अलग-अलग धन शोधन मामलों में उन्हें जारी समन को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर के चरम के दौरान देर रात तक कार्यवाही सहित 45 दिनों तक मैराथन सुनवाई की। चिकित्सकीय ऑक्सीजन पर केंद्र से जवाब मांगा गया। कोरोन वायरस से निपटने के लिए स्थापित पीएम केयर्स फंड भी अदालत की जांच के दायरे में आया, जिस पर केंद्र ने कहा कि यह सरकारी कोष नहीं है क्योंकि दान भारत के समेकित कोष में नहीं जाता है। नए नियमों के तहत अधिकारियों की नियुक्त को लेकर ट्विटर के मामले पर भी सुनवाई हुई। केंद्र ने दावा किया कि नए प्रारूप का पालन नहीं करने पर इंटरमीडियरी के तहत छूट खत्म की जा सकती है। इस साल बाद में कार्यवाही बंद कर दी गई क्योंकि केंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने मुख्य अनुपालन अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। अपनी नई गोपनीयता नीति के बारे में चिंताओं को दूर करते हुए, वाट्सऐप ने उच्च न्यायालय को बताया कि जब तक डेटा संरक्षण कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक यह उपयोगकर्ताओं को अद्यतन नियम का विकल्प चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अक्टूबर में, उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति यह कहते हुए बरकरार रखी कि इसमें कोई अनियमितता या अवैधता नहीं है।

उच्च न्यायालय में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की नई आबकारी नीति को भी चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र का रुख भी पूछा जिसमें उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के कानून को असंवैधानिक घोषित करने का इस आधार पर अनुरोध किया गया कि यह संविधान और उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण के विपरीत है। अवैध हॉकर, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के मामलों, निगम के कुछ श्रेणी के कर्मचारियों के बकाया वेतन जैसे मुद्दे पर भी सुनवाई हुई।

दिल्ली में मासूम बच्चे के अपहरण में किशोर समेत चार गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में दो साल के मासूम के कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने एक किशोर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान जहांगीरपुरी निवासी तनु (20), आजादपुर निवासी विपिन (22) तथा आदर्श नगर के रहने वाले मोहम्मद सलमान (19) के तौर पर की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 22 दिसंबर को सूचना मिली थी कि राजधानी कॉलेज के पास फ्लाईओवर से दो साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) उर्विजा गोयल ने बताया कि तकनीकी सहायता की मदद से एक संदिग्ध की पहचान कर उसे पकड़ा गया।

संपादकीय

बीमार राज्य

देश के राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बाबत नीति आयोग के चौथे सर्वे में जहां दक्षिण भारतीय राज्यों ने बेहतर स्थिति को बनाये रखा है, वहीं उत्तर भारत के राज्य पिछड़ते नजर आते हैं। कुल 24 मानकों के आधार पर तैयार सूचकांकों में केरल पहले की तरह एक नंबर पर रहा, वहीं तमिलनाडु और तेलंगाना दूसरे-तीसरे स्थान पर रहे। उत्तर भारत के बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे नीचे 19वें स्थान पर रहा है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने मानकों में सुधार की दृष्टि से नंबर एक स्थान पाया है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार, यू.पी. से ऊपर हैं। दरअसल, ये आंकड़े वर्ष 2019-20 के हैं, जिसे पूरी तरह कोविड काल नहीं कहा जा सकता। राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं का असली मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करेगा कि कोरोना काल में ये राज्य अपने नागरिकों की जान बचाने में कितने कामयाब हुए। हालांकि, दक्षिण राज्यों में रोगियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत बेहतर सेवाएं प्रदान की गईं। निस्संदेह, केरल स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर स्थिति में है, लेकिन बीस करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की तुलना 3.3 करोड़ आबादी वाले केरल से नहीं की जा सकती। बड़ी आबादी के चलते पिछड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जीडीपी और मानव विकास सूचकांक निचले स्तर पर हैं। लेकिन ओडिशा इस मामले में अपवाद है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से बेहतर प्रशासन व जन भागीदारी से स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। यदि उत्तर भारत के पिछड़े राज्य स्थिति में बदलाव को कटिबद्ध हों तो उन्हें ओडिशा मॉडल का अध्ययन करना चाहिए। कमोबेश देश की राजधानी दिल्ली में भी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसी पिछड़ी होना चिंता की बात है। हालांकि, ये दोनों ही प्रदर्शन सुधार की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्रों में शुमार हैं। बहरहाल, कुल मिलाकर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है।

दरअसल, नीति आयोग का हालिया सर्वे स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को गंभीरता से लेने को कहता है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि उत्तर भारत के राज्यों में शिशु मृत्यु दर व प्रसूति माताओं की मौत का आंकड़ा आज भी ज्यादा क्यों है? यह भी कि अस्पतालों में उपचार की विशेषज्ञता का अभाव क्यों है। चिंता की बात यह है कि कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। जाहिरा तौर पर इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है। इस कमी को दूर करने के गंभीर प्रयासों की जरूरत है। वैसे राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की असली कसौटी कोरोना महामारी होगी, तब पता लगेगा कि राज्यों का प्रशासन अपने नागरिकों को किस हद तक सुरक्षा कवच दे पाया। लब्बोलुआब यही है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दिये जाने की जरूरत है। यहां यह सवाल भी स्वाभाविक है कि सभी राज्यों को स्वशासन एक ही समय मिला। देश के उत्तर व दक्षिण राज्यों की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विरासत एक जैसी है, फिर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में इतना अंतर क्यों है? जिस उ.प्र. समेत उत्तर क्षेत्र ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिये, ये इलाके राजनीतिक रूप से जागरूक भी हैं, ज्यादा आबादी के चलते इनका राजनीतिक दबदबा भी कायम रहा तो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति इतनी बदतर क्यों? क्या 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' का फार्मूला छोटे-बड़े राज्यों पर लागू होता है? क्या उत्तर भारत में विकास के मुद्दों के बजाय भावनात्मक मुद्दों व संकीर्णता की राजनीति की सजा इन राज्यों की स्वास्थ्य सेवाएं भुगत रही हैं? निस्संदेह जिन राज्यों में वैचारिक व धार्मिक सहिष्णुता की स्थिति संतोषजनक रही है, वहां विकास को नये आयाम भी मिले हैं। ऐसे में उत्तर भारत के बीमारू राज्यों को रचनात्मक विकास को तरजीह देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा। हाल ही के कोरोना संकट ने इसकी कमी का अच्छी तरह अहसास कराया, जब दवाओं, बेड व आक्सीजन के अभाव में लोग तिल-तिल कर मरते रहे।

धर्म संसद के बहाने

इन दिनों हिंदूवादी संस्था धर्म संसद गहरे विवाद में है। ताजा विवाद रायपुर में आयोजित धर्म संसद से संबंधित है, जिसमें कथित संत कालीचरण ने अपने भाषण में मुसलमानों के प्रति विद्वेषभरी बातें कहीं और साथही महात्मा गांधी को मुस्लिम परस्त और देश के विभाजन का जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी हत्या के दुष्कृत्य को उचित ठहरा दिया और नाथूराम गोड़से को महिमामंड़ित कर दिया। अपने भाषण में हिंदुओं की कीमत पर पाकिस्तान के निर्माण तथा पड़ोसी इस्लामी देशों में हिंदुओं की बदतर स्थिति पर टिप्पणी करते हुए इस्लाम को देश के लिएखतरा बताया और हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान भी कर दिया। इस तरह के विचार मात्र एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत तौर पर व्यक्त किए गए विचार नहीं हैं। हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो गांधी को देश विभाजन का जिम्मेदार मानता है। दूसरे अर्थ में पाकिस्तान के निर्माण में सहायक मानता है। उनका यही तर्क नाथूराम गोड़से को सही ठहरा देता है। अब प्रश्न यह है कि अगर भारत में यह विचार फैल रहा है तो यह अकारण नहीं है। इसके मूल में बहुत कुछ है। देश के विभाजन में जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत गढ़ा गया था, उसकी काट न तो स्वतंत्रता आंदोलन से निकली, न गांधी के नेतृत्व से निकली और न ही कांग्रेस की विचारधारा से निकली। गांधी की हत्या के बाद देश पर शासन करने वाले नेतृत्व की यह अहम जिम्मेदारी बनती थी कि वह विभाजन के पीछे के विचारों को ऐतिहासिक तौर पर संज्ञान में लेता और गांधी के विचार से केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भी जोड़ने का कार्यक्रमबद्ध आंदोलन चलताग लेकिन उन्होंने देश के विभाजन को ऐसी घटना के रूप में लिया जो उनकी नजर में पूर्ण होकर निष्प्रभावी हो गई थी। उन्होंने इस्लामी कट्टरता का कभी कोई वैचारिक-सांस्कृतिक प्रतिरोध खड़ा नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि दुनिया भर में जिस इस्लामी कट्टरपंथ का उदय हुआ और भारत में जिस तरह आतंकवादी हमले हुए, उसने भारत के उदार हिंदुओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल दिया। संत कालीचरण, स्वामी धरमदास और साध्वी अन्नपूर्णा को गिरफ्तार करना और उन पर मुकदमा चलाना एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन यह समझना होगा कि समस्या जितनी गंभीर हैग उसके लिए उतनी ही गंभीर और व्यापक सोच की जरूरत है।

कटाक्ष/ सहीराम

एक और मुलाकात

वर्षों बाद एक बार फिर मुन्ना भाई और गांधी जी की मुलाकात हुई। इन दिनों गांधी जी को पड़ रही गालियों से मुन्ना भाई काफी परेशान थे, लेकिन गांधी जी एकदम प्रसन्न मुद्रा में थे। बड़े खुश नजर आ रहे हो बापू-मुन्ना भाई ने थोडवी नाराजगी से कहा। हां-बापू ने कहा-गालियां सुनकर आ रहा हूं न इसलिए खुश हूं। क्या धर्म संसद से आ रहे हो-मुन्ना भाई आश्चर्यचकित थे। नहींग गालियां सुनने के लिए धर्म संसद जाने की क्या जरूरत है। गालियां देने वाले तो भैया असली संसद तक पंहुच गए हैं। वो संसद पंहुच तो गए हैं बापू-मुन्ना भाई ने कहा-पर प्रधानमंत्री जी ने उन्हें दिल से माफ नहीं किया। चलो, अब प्रधानमंत्री जी को अपना दिल साफ कर लेना चाहिए। क्योंकि वे भी कितनों को दिल से माफ न करने का गिला लिये बैठे रहेंगे। तादाद तो निरंतर बढ़ ही रही है न। ऐसे में किसी संसद में जाने की जरूरत ही क्या है! गालियां तो टीवी चैनलों की प्राइम टाइम डिबेटों में भी आराम से सुनी जा सकती हैं। आजकल खूब जी भर कर गालियां पड़ रही हैं। वो लोग आपको कोस रहे हैं, हरामी कह रहे हैं और आप फिर भी खुश हैं बापू-मुन्ना भाई ने फिर नाराजगी दिखाई। तुम मानोगे नहीं-बापू ने कहा-लेकिन इससे मेरी उम्र बढव जाती है बच्चे। मैं समझा नहीं बापू-मुन्ना भाई ने माथा पकड़ते हुए कहा। देखो-बापू ने कहा-मैं सवा सौ साल जीना चाहता था। मेरी इस चाहत से वे ऐसे डरे कि मुझे अस्सी तक भी न पंहुचने दिया। तुम्हें शायद पता नहीं होगा मुझे मार कर वे इतने खुश थे कि उन्होंने लड्डू तक बांट दिए थे, लेकिन हुआ क्या? लेकिन बापू-मुन्ना भाई ने कहा-मैंने जो गांधीगिरी शुरू की थी, वह तो दस साल भी नहीं चल पाई और गोडसेगिरी शुरू हो गई। आज गोडसे की जय-जयकार हो रही है। मैं तो चलो एक गली का गुंडा था, लेकिन यह कैसे साधु-संत हैं बापू, जो गोडसे को भगवान बना रहे हैं, और आपको राक्षस। अरे तुम उदास मत हो मुन्ना भाई-बापू ने कहा-जैसे तुमने लड़-झगडक्कर मुझे इन्वेंट किया था। वैसे ही वे भी गालियां देकर-कोसकर मुझे नये सिरे से इन्वेंट ही कर रहे हैं। जब मेरी हत्या कर उन्होंने सत्तर साल मेरी उम्र बढव दी थी तो गाली-गलौच से भी दस-बीस साल तो बढ़ ही जाएगी न। नहीं क्या मुन्ना भाई! और गांधी जी चले गए। शायद और ज्यादा गालियां सुनने के लिए!

नव वर्ष विशेष: भारत में नववर्ष की अनूठी परंपराएं

श्वेता गोयल

देश में जिस प्रकार दीवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व इत्यादि अनेक त्यौहार बड़ी धूमधाम, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही उत्साह लोगों में नववर्ष के अवसर पर भी देखा जाता है। नव वर्ष के प्रथम दिन लोग एक-दूसरे को बधाई देते हैं और स्वयं के लिए भी कामना करते हैं कि नया साल शुभ एवं फलदायक हो, नए साल में सफलता उनके कदम चूमे तथा नव वर्ष उनके जीवन को खुशियों से महका दे।

नए साल के आगमन की खुशी में लोग नव वर्ष की पूर्व संध्या पर नाचते-गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। नाच-गाने का यह सिलसिला घड़ी में रात्रि के 12 बजने अर्थात् नव वर्ष के आरंभ होने तक चलता है और घड़ी की सुईयों द्वारा जैसे ही 12 बजने का संकेत मिलता है अर्थात् नया साल दस्तक देता है, चहु ओर आतिशबाजियों का धूमधड़ाका शुरू हो जाता है। एकबारगी तो यही अहसास होता है कि मानो डेढ़-दो माह बाद एक बार फिर से दीवाली का त्यौहार लौट आया हो।

दुनिया भर में नव वर्ष का स्वागत बड़ी धूमधाम, उमंग और उल्लास के साथ किया जाता है। अनेक देशों में नववर्ष से जुड़ी अपनी-अपनी परंपराएं हैं। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी नववर्ष का स्वागत अलग-अलग तरीके से किया जाता है लेकिन कई जगह नव वर्ष मनाने की परंपराएं और रीति-रिवाज इतने विचित्र हैं कि लोग उनके बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। संभवतः दुनिया भर में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां नव वर्ष एक से अधिक बार और विविध रूपों में मनाया जाता है। हमारे यहां ईस्वी संवत् और विक्रमी संवत् दोनों को ही महत्व दिया जाता है। ईस्वी संवत् के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत एक जनवरी को और विक्रमी संवत् के अनुसार नए साल की शुरूआत वैशाख माह के प्रथम दिन से मानी जाती है जबकि इस्लाम में हिजरी संवत् के आधार पर नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है।

> "व्यापारी समुदाय के लोग अपने आर्थिक हिसाब-किताब की दृष्टि से दीवाली से ही नववर्ष की शुरूआत मानते हैं जबकि वित्तीय आधार पर शासकीय नववर्ष की शुरूआत एक अप्रैल से होती है।"

बहरहाल, नव वर्ष मनाने की परंपराएं चाहे कुछ भी हों, सभी का उद्देश्य एक ही है और वह है नव वर्ष सुख, शांति एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो। आइए जानते हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों में कैसे मनाया जाता है नव वर्ष:

महाराष्ट्र में नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक सप्ताह पहले ही घरों की छतों पर रेशमी पताका फहराई जाती है। घरों व दफ्तरों को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जाता है तथा इस दिन पतंगें उड़ाकर नव वर्ष का स्वागत किया जाता है।

बिहार में नव वर्ष के मौके पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा-अर्चना की जाती है। गरीब बच्चों को कपड़े तथा चावल का दान किया जाता है ताकि वर्ष भर घरों में सुख-शांति एवं समृद्धि बनी रही।

असम में नव वर्ष की यादगार बेला में घर के आंगन में मांडणे (रंगोली) सजाए जाते हैं तथा दीप या मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। गाय को रोटी और गुड़ खिलाया जाता है ताकि नव वर्ष हंसी-खुशी के साथ गुजरे।

केरल में नव वर्ष के अवसर पर नीम व तुलसी की पत्तियां तथा गुड़ खाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इनको खाने से शरीर साल भर तक स्वस्थ बना रहता है।

राजस्थान में नव वर्ष के विशेष अवसर पर गुड़ से बने पकवान खाना बहुत शुभ माना जाता है ताकि वर्षभर मुंह से मधुर बोली ही निकलती रहे।

मणिपुर में इस दिन तरह-तरह की आतिशबाजी की जाती है तथा अनेक स्थानों पर भूत-प्रेतों के पुतले बनाकर भी जलाए जाते हैं ताकि भूत-प्रेत किसी को नुकसान न पहुंचा सकें।

छत्तीसगढ़ में यहां के आदिवासी समाज के लोग तरह-तरह के गीत गाकर नव वर्ष का स्वागत करते हैं। इस दिन यहां बच्चों को गोद लेने की प्रथा भी है ताकि वर्ष का प्रत्येक दिन खुशियों से भरा रहे। राज्य के कुछ आदिवासी इलाकों में फसल में महुआ के फूल दिखाई देने पर आदिवासी उत्सव मनाया जाता है, जो उनके नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। देश के कई अन्य आदिवासी इलाकों में उनके देवी-देवताओं के आराधना पर्वों के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है।

जम्मू कश्मीर में नव वर्ष के उपलक्ष्य पर अनाथ बच्चों को भरपेट भोजन कराकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उनके माथे पर तिलक लगाकर आरती उतारी जाती है ताकि नव वर्ष हंसी-खुशी के साथ व्यतीत हो सके।

नागालैंड के नाग आदिवासी नाग पंचमी के दिन से ही अपने नव वर्ष की शुरुआत करते हैं।

कृषि प्रधान राज्यों पंजाब तथा हरियाणा में यूं तो आजकल एक जनवरी को ही नव वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है किन्तु यहां नई फसल का स्वागत करते हुए नव वर्ष वैसाखी के रूप में भी मनाया जाता है।

व्यापारी समुदाय के लोग अपने आर्थिक हिसाब-किताब की दृष्टि से दीवाली से ही नववर्ष की शुरूआत मानते हैं जबकि वित्तीय आधार पर शासकीय नववर्ष की शुरूआत एक अप्रैल से होती है।

मॉब लिंचिंग

भीड़ के अन्याय से कशमशाती इंसानियत

दीपिका अरोड़ा

गत 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा में 'मॉब वॉयलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल, 2021' पारित किया गया, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सामूहिक हिंसा रोकना है। इसके तहत दो या दो से अधिक लोगों द्वारा हिंसा करना मॉब लिंचिंग माना जाएगा। भीड़ हिंसा के दोषी पाए जाने पर जुर्माने तथा संपत्तियों की कुर्की के अलावा तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान है। हिंसा में पीड़ित की मृत्यु होने पर दोषी को आजीवन कारावास तथा 5 से 25 लाख तक जुर्माने की सज़ा होगी। भड़काऊ पोस्ट डालने तथा पीड़ितों व गवाहों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने वाले लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। किसी का सामाजिक अथवा व्यावसायिक बहिष्कार भी मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आएगा। पीड़ितों के लिए इसमें मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात यह कानून बनकर राज्य में प्रभावी हो जाएगा।

अक्सर प्रकाश में आने वाले सामूहिक हिंसा मामलों ने, 2019 में झारखंड में व्यापक चर्चा तब पकड़ी, जब 24 वर्षीय तबरेज़ अंसारी को बकरी चोरी के संदेह में सरायकेला खरसावां जिले की भीड़ ने रस्सी से बांधकर इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय की फटकार के पश्चात ऐसे मामलों के निपटारे हेतु जिला स्तरीय समितियों के गठन का फैसला किया गया।

'अनेकता में एकता' भारतीय संस्कृति की विशेषता है, किंतु विविधता में समाविष्ट मतभेदों का हिंसात्मक प्राकट्य राष्ट्रहित के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 'मॉब लिंचिंग' अर्थात? उत्तेजित भीड़ द्वारा किसी को दोषी पाए जाने पर या अपराधी होने के संदेह में स्वयं दंड देना, लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिगोचर होना गहन चिंता का विषय है। वर्ष 2002 में हरियाणा के पांच दलितों को गोहत्या के आरोप में सामूहिक हिंसा का निशाना बनाया गया। 2015 में अज्ञात समूह ने मोहम्मद अखलाक को, बेटे

दानिश सहित, गोहत्या तथा मांस-भंडारण के आरोप में पीटकर मार डाला। 2017 को राजस्थान में गो तस्करी के झूठे आरोप में पहलू खान की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र के पालघर में क्रुद्ध भीड़ द्वारा तीन साधुओं को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया। किसान आंदोलन के दौरान सिंघु बॉर्डर पर कथित बेअदबी आरोपी को तेजधार हथियारों से काट दिया गया। हाल ही में पंजाब की दो कथित 'बेअदबी' घटनाओं में आरोपितों को पीट-पीटकर मार डाला गया। अनुमानतः वर्ष 2019 में 107 व 2020 में 23 'मॉब लिंचिंग' मामले प्रकाश में आए।

लिंचिंग की अधिकांश घटनाएं जातिगत भेदभाव व धार्मिक असहिष्णुता से संबद्ध हैं। विचाराधीन मामलों का समय पर निपटारा न होना भी घटनाओं की बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण है, जैसा कि पंजाब के 'लंबित बेअदबी मामलों' में देखने को आया। जनप्रतिनिधियों के भड़काऊ भाषण तथा स्वार्थसिद्धि हेतु राजनीतिक हथकंडों के रूप में बल प्रयोग भी सामूहिक हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। हालिया कपूरथला मॉब लिंचिंग में सोशल मीडिया का गैर-जिम्मेदाराना रवैया भी प्रमुख कारण के रूप में सामने आया।

भारतीय दंड संहिता में 'मॉब लिंचिंग' के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। इनका निपटारा धारा-302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 323 (जानबूझकर घायल करना), 147-148 (दंगा-फसाद), 149 (आज्ञा के विरुद्ध एकत्रित होना) तथा धारा-34 (सामान्य आशय) के तहत होता है। भीड़ द्वारा हत्या करने पर आईपीसी की धारा 302 तथा 149 मिलाकर पढ़ी जाती हैं, हत्या- प्रयास मामले में धारा 307 और 149 संयुक्तरूपेण सम्मिलित होती हैं। सीआरपीसी में भी इस बारे स्पष्टतः कुछ नहीं कहा गया।

'भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता', लिंचिंग में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी न हो पाना सबसे बड़ी समस्या है। न केवल यह अनुच्छेद-21 में दिए 'जीवन के अधिकार' का हनन करता है, बल्कि दुस्साहसी प्रवृत्ति का उत्साहवर्द्धन करते हुए राज्य की कानूनी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के 2019 के आंकड़ों के अनुसार, 163 देशों में भारत का स्थान 141वां रहा।

वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने लिंचिंग को 'भीड़तंत्र के एक भयावह कृत्य' के रूप में संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को कानून बनाने के दिशा-निर्देश दिए। मणिपुर, वर्ष 2018 में लिंचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना। तार्किकता व प्रासंगिकता के मद्देनजर यह विधेयक सराहनीय आंका गया। 2019 में राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल में भी लिंचिंग के विरुद्ध विधेयक पारित किए गए।

मॉब लिंचिंग न केवल सामाजिक भ्रातृत्व, मानवीय सौहार्द के लिए घातक है बल्कि राज्य की आंतरिक अस्थिरता का कारक भी है। इससे आम जनता में असुरक्षा, भय व अशांति की भावना उपजती है तथा पुलिस प्रशासन व कानून व्यवस्था के प्रति रोष एवं संदेह उत्पन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होने से विदेशी व घरेलू निवेश प्रभावित होते हैं, जिसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वनिर्धारित दंड-प्रक्रिया का यह घृणित स्वरूप समूची मानवता के लिए एक विषैला दंश है। लोकतंत्र पर भीड़तंत्र का हावी होना मानवीय, सामाजिक, नैतिक, कानूनी; किसी भी आधार पर क्षम्य नहीं। अन्य राज्यों को भी इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए।

उत्तर प्रदेश

योगी के मंत्र से सुधरता स्वास्थ्य तंत्र

गिरीश पांडेय

स्वास्थ्य (चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा) क्षेत्र योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा क्षेत्र रहा है। दरअसल, 1998 से 2017 तक उन्होंने गोरखपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया। गोरखपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र (नेपाल से सटे से लेकर बिहार तक) तराई का है। इस इलाके में मच्छरों की बहुलता है। चंद फीट की गहराई में पानी उपलब्ध होने के कारण प्रदूषित भी है। ऐसे में करीब 6 से 7 करोड़ लोगों की आबादी वाला यह इलाका मच्छर और जलजनित रोगों (इंसेफेलाइटिस, एईएस, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया आदि) के प्रति संवेदनशील है। इंसेफेलाइटिस एवं एईएस से हर साल सैकड़ों-हजारों की संख्या में मौत होती रही हैं। मरने वालों में अधिकांश मासूम रहते थे। मौतों से अधिक संख्या शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग होने वालों की रही है।

योगी इन सबके साक्षी रहे हैं। यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक जो संघर्ष किया उससे हर कोई वाकिफ है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस क्षेत्र में उनकी रु चि का सिलसिला जारी रहा। हालांकि देश के सर्वाधिक आबादी वाले प्रदेश में संसाधन अपेक्षाकृत कम हैं, और पिछली सरकारों द्वारा चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में इसकी अनदेखी की गई। जो ठान लिया उसे अंजाम तक पहुंचाना योगी की फितरत है। इंसेफेलाइटिस पर लगभग नियंत्रण कर उन्होंने इसे साबित भी किया। आम नागरिक को पास में सस्ता, बेहतर और अद्यतन इलाज मिलेग इसके लिए भी वे सतत प्रयासरत रहे हैं। गोरखपुर में 1011 करोड़ रुपये की लागत से 112 एकड़ के विस्तृत रकबे पर अखिल भारतीय आयुतवज्ञान संस्थान (एम्स) और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के परिसर में रिजनल मेडिकल रिचर्च सेंटर (आरएमआरसी), दोनों विश्वस्तरीय संस्थानों का लोकार्पण 7 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर चुके हैं। इसके पहले 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में प्रदेश के इकलौते आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। गोरक्षपीठ की तरफ से बने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में भी मेडिकल एवं पैरा मेडिकल शिक्षा की शानदार व्यवस्था है। इंस्टीटूट ऑफ मेडिकल साइंस भी जल्द क्रियाशील हो जाएगा। ये सभी संस्थान पूरे क्षेत्र में होने वाले मौसमी, संचारी एवं गंभीर रोगों के इलाज, इन रोगों की वजहों पर शोध और तद्नुसार इनके नियंत्रण में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की भी है। अभी 59 जिलों में प्रदेश सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, बन रहे हैं, या निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन हैं।

अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ यूपी के नौ नये राजकीय मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया था। नये मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बने हैं, या बन रहे हैं। प्रदेश के 16 जिलों (बागपत, हाथरस, रामपुर, संभल, शामली, महाराजगंज, कासगंज, मऊ, श्रावस्ती, चित्रकूट, बलिया, भदोही, हमीरपुर, महोबा, मैनपुरी और संत कबीरनगर) में भी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की कार्ययोजना बनाई जा चुकी है।

मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही यूपी मेडिकल उपकरणों का भी महद्मवपूर्ण हब बनने जा रहा है। राज्य में बड़े निवेशकों के जरिए यूपी को मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग तथा दवा निर्माण का हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता में आते ही कार्य शुरू किया था। इसके तहत उन्होंने राज्य में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। दवाओं के निर्माण के लिए भी सरकार ने बीते माह कई फैसले किए हैं जिसके चलते 2018 में बनी फार्मास्यूटिकल नीति में संशोधन कर नई फार्मास्यूटिकल नीति लाने का फैसला किया है। इससे कच्चे माल के रूप में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) निर्माण करने वाली कंपनियों ने यूपी में आने की पहल की है। जल्दी ही दवा निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत देश-विदेश की बड़ी दवा कंपनियां भी यूपी में आएंगी। इससे दवाओं के कच्चे माल के आयात के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी और यूपी दवा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जारी प्रयासों के चलते मात्र आठ महीनों में साढ़े पांच सौ से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए कोविड टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों तथा बेड की संख्या में इजाफा किया गया है। योगी के इन प्रयासों की तारीफ नीति आयोग भी करने लगा है। बीते सोमवार को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के उन बड़े राज्यों में शीर्ष पर है, जिनके स्वास्थ्य तंत्र में उल्लेखनीय सुधार आया है। स्वाभाविक रूप से यह बदलाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही आया है। लिहाजा, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI NO. DELHIN38334, E-mail:gauravashalibharat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

सार समाचार

15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 357450 बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी कोविड वैक्सीन

शिमला। कोविड टीकाकरण के लिए गठित राज्य कार्य बल समिति की बैठक आज यहां स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सहरूग्णता वाले लोगों को कोविड टीके की तीसरी एहतियातन खुराक देने की तैयारियों की समीक्षा की गई। अमिताभ अवस्थी ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णय के अनुसार प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण 3 जनवरी, 2022 से प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवीं से बाहरवीं कक्षा के 357450 लाभार्थियों को 2797 राजकीय पाठशालाओं में यह टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को को-वैक्सीन दी जाएगी। इस आयु वर्ग के पात्र बच्चे कोविन पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर टीके के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं अथवा अपने मोबाइल नम्बर के माध्यम से नया खाता खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि समीपवर्ती राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में ऑनलाइन अथवा मौके पर ही टीके के लिए समय निर्धारण करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दोनों टीके लगवा चुके स्वास्थ्य कार्यकताओं, फ्रंट लाईन वर्कर और सहरूग्णता वाली 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की पात्र आबादी को 10 जनवरी, 2022 से कोविड टीके की एहतियातन खुराक प्रदान की जाएगी। इसके लिए टीके की दूसरी खुराक लेने की तिथि से 39 सप्ताह अथवा 9 माह की अवधि पूर्ण कर चुके लोगों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ग में 96200 पात्र आबादी को एहतियातन खुराक दी जाएगी जिनमें 32663 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 61431 फ्रंट लाईन वर्कर और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की दूसरी खुराक ले चुकी सहरूग्णता वाले 10530 लोग शामिल हैं।

तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली-एनसीआर और यूपी में नए साल के जश्न पर पाबंदी, इस राज्य ने सेलिब्रेशन के लिए दी विशेष छूट

नई दिल्ली। ओमिक्रोन के खौफ के बीच देश में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो गई है। कोरोना के दैनिक मामले दस हजार के पार पहुंच गए हैं वहीं ओमिक्रोन के मामले भी एक हजार के करीब पहुंच चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश में संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा बढ़ा दिया है। देश में बढ़ते कोरोना की रफ्तार के बीच दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और यूपी में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जिसने न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए लोगों को विशेष छूट प्रदान की है। ये राज्य है राजस्थान जहां प्रदेश सरकार की तरफ से कर्फ्यू में राहत दी गई है। गाइड लाइन में 31 दिसंबर की रात को जश्न मनाने के लिए छूट दी गई है।

नये साल पर कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट

राजस्थान में सामान्य दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन नये साल की रात एक बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। इधर सरकार ने बढ़ते सक्रमण को देखते हुए शादी-समारोह में मेहमानों की संख्या 200 तक सीमित कर दी है। वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स ऑडिटोरियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे। वैक्सीन की अनिवार्यता भी नए साल के बाद रखी गई है। नए साल के बाद कॉलेज, सिनेमा और होटल में वैक्सीन की डबल डोज लगाने वालों को ही एंट्री मिलेगी।

कोरोना के मामले बढ़े

बता दें कि राजस्थान सरकार टूरिस्टों के प्रदेश में भारी तादाद में आने के बावजूद इस तरह की रिस्क ले रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच दिनों में जयपुर में 60 हजार टूरिस्ट आए हैं। वहीं अगर प्रदेश में कोरोना केस की बात करें तो कोरोना से संक्रमित मरीजों के रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों के आंकड़ों की बात की जाए तो 5 गुना से भी ज्यादा संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। जयपुर शहर में 1 सप्ताह के दौरान 237 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं।

नए विवाह कानून वाला बिल पास होने के डर से हड़बड़ी में मुस्लिम परिवार, हैदराबाद की मस्जिदों में निकाह के लिए लगी लंबी कतारें

नई दिल्ली। हैदराबाद के मस्जिदों में निकाह के लिए लंबी लाइन चल रही है। इसकी वजह है मोदी सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के लिए कानून का लाया जाना। जिसकी वजह से मुस्लिम परिवार हड़बड़ी में दिख रहे हैं और कानून लागू होने से पहले निकाह कर लेना चाहते हैं। जल्दबाजी में किए गए इन समारोहों में शामिल सभी दुल्हनों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है। अधिकांश की शादी 2022-2023 में किसी समय होनी थी, लेकिन बिल पास होने के डर ने उनके परिवारों को तब तक इंतजार नहीं करने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी समुदायों पर लागू होने वाला यह बिल महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करता है।

जल्दबाजी में परिवार

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 19 साल के एक बच्चे की मां समरुन्निसा ने कहा कि मेरी तीन बेटियाँ हैं। उनमें से एक विकलांग है। मैं उनमें से कम से कम एक की शादी करने के लिए और दो साल का इंतजार कैसे कर सकता हूं। उन्होंने अपनी बेटी को निकाह के लिए एक स्थानीय मस्जिद लेकर गईं। बाबानगर निवासी ने कहा कि हमने 2022 के मध्य में समारोह आयोजित करने की योजना बनाई थी क्योंकि उसके पिता हाल ही में नौकरी की तलाश में श्रीलंका गए थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि वह शादी की व्यवस्था करने के लिए कुछ पैसे लेकर वापस आएंगे। लेकिन जब हमने बिल के बारे में सुना, तो हमें जल्दबाजी दिखानी पड़ी।

विदाई अभी नहीं हो रही

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने ओल्ड सिटी में रहने वाले कम से कम आधा दर्जन परिवारों से बात की, जिन्होंने इसी कारण से अपनी बेटियों की शादी की तारीखों को आगे बढ़ाया है। हालांकि लगभग सभी मामलों में, वित्तीय कारणों से 'विदाई' को टाल दिया गया है। 2020 के लॉकडाउन के दौरान ड्राइवर की नौकरी गंवाने वाले रहमत अली का कहना है कि यह अनिवार्य है कि हम अपनी बेटी को कुछ फर्नीचर, सोना, कपड़े और नकदी के साथ उसके ससुराल भेज दें। लेकिन अभी, मैं परिवार के लिए भोजन कमाने के लिए भी संघर्ष कर रहा हूं।

ओमिक्रॉन ने फीका किया न्यू यार का जश्न, रात 10 बजे तक शहर में सभी पार्टियां होंगी बंद

वाराणसी। ओमिक्रॉन का खतरा इस बार नए साल की चमक को फीका कर देगा। इस बार युवाओं को रात में रोड पर घूमना महंगापड़ सकता है, जी हां, वाराणसी जिला प्रशासन के पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से आदेश जारी किए गए है की, रात्रि दस बजे के बाद किसी भी क्लब, रेस्टोरेंट या होटल में कोई भी न्यू ईयर पार्टी नहीं मनेगी, और आदेश के उलंघन पर जुमार्ना लग सकता है। क्लब, रेस्टोरेंट की न्यू ईयर पार्टी के साथ ही आवासीय परिसर या अपार्टमेंट में भी न्यू ईयर के दिन दस बजे के बाद गाने और डीजे पर पाबंदी है। आदेश के सख्त पालन के लिए, सभी थानों को निर्देश दिए जा चुके है।प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से ही ग्रामीण इलाकों में भी रात्रि दस बजे तक सभी दुकानें बंद कर दी जा रही है, और लोग अपने घरों में चले जा रहे है। अपर पुलिस आयुक्त अपराध व मुख्यालय सुभाष चंद्र दुबे ने मीडिया से मुखातिब हो बताया कि, शहर में रात्रि दस बजे तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और क्लब बंद होने के आदेश है, जो 31 दिसंबर की रात भी लागू रहेंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि, वह न्यू ईयर का जश्न अपने घरों में परिवारजनों के संग ही मनाए।

उत्तराखंड की धरती से पीएम मोदी का पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला, बोले- विकास परियोजनाओं को 4 दशक तक लटकाया

हल्द्वानी। (एजेंसी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर सुविधाएं देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो कई पुरानी यादें ताजा हो गईं हैं। ये इतनी आत्मीयता से आपने जो उत्तराखंडी टोपी मुझे पहनाई गई है, वो उसे पहनकर मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हल्द्वानीवालों के लिए एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। उत्तराखंड में बढ़ रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उत्तराखंड में बढ़ रही औद्योगिक क्षमता, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण उत्तराखंड की धरती पर ही खींच कर लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, होम स्टे अभियान इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाकर रहने वाले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम हिमाचल की ताकत को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती हैं। आजादी के बाद से ही, यहां के लोगों ने दो धाराएं और देखी हैं। एक धारा है- पहाड़ को विकास से वंचित रखने की और दूसरी धारा है- पहाड़ के विकास के लिए दिन रात एक कर देने की। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। आज उधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सेटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है।

उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में करीब 9,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट सड़क निर्माण से जुड़े हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1,200 किमी ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। इन सड़कों के अलावा उत्तराखंड में 151 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।

इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले सरकार में रहने वाले लोगों को आपकी चिंता होती तो क्या यह परियोजनाएं चार दशक तक लटकती क्या ? अगर उनका आपके प्रति प्यार था तो क्या काम की यह दुर्दशा होती क्या ? सच्चाई यही है कि पहले जो सरकार में थे उन्होंने उत्तराखंड के सामर्थ्य की कभी परवाह नहीं की। परिणाम यह हुआ कि हमें पर्याप्त बिजली नहीं मिली, किसानों के खेतों को सिंचाई नहीं मिली और देश के अधिकतर ग्रामीणों को पानी के अभाव में जीवन गुजरना पड़ा।

कश्मीर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी नागरिक समेत जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग-अलग मुठभेड़ों में एक पाकिस्तानी नागरिक समेत जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी मारे गए जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में यह मुठभेड़ हुई।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आतंकियों की मौजूदगी के बारे में मिली खुफिया सूचना के आधार पर कुलगाम जिले के मीरहमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया और इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके साथ मुठभेड़ शुरू हो गयी।
इस मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे। पुलिस महानिरीक्षक ने एक ट्वीट में कहा, इस मुठभेड़ में दो स्थानीय आतंकवादी जबकि एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया है। ये तीनों आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य थे। इनके पास से एक एम-4 जबकि दो एके-47 राइफलें भी बरामद की गयी हैं।
सुरक्षाबलों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग जिले के दूरु के नौगांम शाहबाद में सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई।

अयोध्या और काशी में भव्य निर्माण हो रहा है फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा : योगी

अमरोहा (उत्तर प्रदेश) (एजेंसी)

अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण शुरू कराने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे में 'मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा।' मुख्यमंत्री ने बुधवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया। उन्होंने कहा, हमने जो कहा, करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराएंगे। (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है, उससे आप सभी खुश हैं। अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रुप में बन रहा है।' उन्होंने कहा, 'ऐसे में मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी (सपा) को कांवड़ यात्रा रोकने और दंगाइयों को बढ़ावा देने वाली पार्टी करार देते हुए आज कहा कि अयोध्या, काशी या मथुरा हो, भाजपा ने जो कहा वह काम पूरा किया। योगी अमरोहा में 43 करोड़ रुपए की 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'जन विश्वास यात्रा' के दौरान अपने संबोधन में सपा पर निशाना साधते हुए कहा, जो रामभक्तों पर गोली चलाते थे। जो कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगाते थे। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे। इनसे आप कोई अच्छी उम्मीद करते हैं क्या। प्रदेश को तबाह करना इनकी नियति थी। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने आस्था का भी सम्मान किया है और जनता का विकास भी किया है। उन्होंने आरोप लगाया, 'सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। कांग्रेस का तो कोई रहनुमा ही नहीं था। भाजपा के लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है। उसने इस परिवार की खुशहाली को ध्यान में रखकर ही अपनी योजनाएं बनाई हैं।' योगी ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगाइयों से मुक्त कराने का वादा जो किया था वह हमने पूरा किया है। 2017 के पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था। कोई निवेश नहीं करना चाहता था, नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, दंगाइयों को रोका नहीं जाता था। अब समय बदला है। अब यहां दंगा नहीं गन्ना उगाया जा रहा है।

माउंट आबू का हो योजनाबद्ध विकास : गहलोत

जयपुर (एजेंसी)

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि माउंट आबू राजस्थान का एक मात्र पवर्तीय पर्यटक स्थल है और इसके योजनाबद्ध विकास के लिए पर्यटन विभाग और स्वायत्त शासन विभाग योजना बनाए, ताकि इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि माउंट आबू विकास समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए। गहलोत बुधवार को आबू पर्वत नगर पालिका के शरद महोत्सव-2021 के उद्घाटन तथा लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील पर गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण तथा महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि करीब तीस साल से मनाए जा रहे शरद महोत्सव को और भी आकर्षक एवं वृहद स्तर पर आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पहली बार 500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाया गया है। इस कोष से पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, उनके संरक्षण तथा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत ब्रांडिंग जैसे कार्य किए जाएंगे।

केजरीवाल ने सभी पार्षदों को दिलाई AAP नहीं छोड़ने की शपथ, बोले- चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर दिया वोट

चंडीगढ़। (एजेंसी)

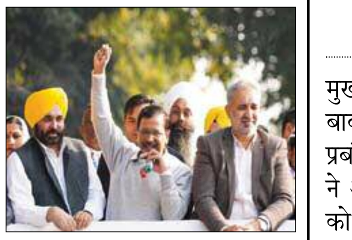

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए गुरुवार को विजय मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजें आए हैं लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। चंडीगढ़ के लोगों ने दिल्ली को देखकर वोट दिया। जैसे दिल्ली को देखकर और जगह वोट मिल रहा है। अब चंडीगढ़ में इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देखकर देश की बाकी जनता हमें वोट दें। दिल्ली हमें पहला राज्य मिला था और चंडीगढ़ में पहली नगरपालिका मिली है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के एक-एक पार्षद के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। मैं सभी पार्षदों से कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय राजनीति होती है और अब चुनाव खत्म हो गया है। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल वाले सभी अपने हैं और हमें सभी का काम करना है। उन्होंने कहा कि अकाली दल का कोई वोटर है या फिर भाजपा का उनका हमें ज्यादा काम करना है, ताकि अगली दफा वो हमें ही वोट दें। इसी बीच केजरीवाल ने सभी 14 पार्षदों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की कसम खाता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों की तन, मन और धन से पूरी तरह सेवा करूंगा। जो विश्वास चंडीगढ़ के लोगों ने मुझपे किया है, उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा और न ही किसी को गलत काम करने दूंगा। आम आदमी पार्टी मेरी मां के समान है और चंडीगढ़ के लोग मेरे परिवार के समान है। इसके साथ ही केजरीवाल ने पार्षदों को आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाने की शपथ भी दिलाई।

कोरोना में भी प्रदेश सरकार ने वित्तीय प्रबंधन बनाए रखा अच्छा: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ । (एजेंसी)

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के बावजूद हरियाणा सरकार ने अपना वित्तीय प्रबंधन अच्छे से बनाए रखा है। प्रदेश सरकार ने आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए अलग से रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण से प्री-बजट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को प्री-बजट की बैठक में सुझावों के लिए बुलाया था। हरियाणा सरकार ने उसने मांग की है कि जैसे नाबार्ड, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.75 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देता है, उसी तरह एनसीआर प्लॉनिंग बोर्ड के तहत भी 2.75 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। ताकि एनसीआर के क्षेत्र में तेज गति से विकास हो सके। इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार ने जीएसटी के लिए हाईब्रेड मॉडल बनाए जाने की मांग रखी है, जिसमें खपत के साथ-साथ उत्पादन शेयर भी सम्मलित किया जाए। इससे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने हिसार में स्थित राखीगढ़ी के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा स्कीम के माध्यम से ऋण मिल रहा है। इसमें ब्याज माफी की योजना बनाई जाए। एफपीओ के लिए ऋण की सीमा फिलहाल 2 करोड़ रुपये है, इसे बढ़ाना चाहिए, ताकि प्रदेश में बड़े फूड प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट लगाए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई का विस्तार हो रहा है। केंद्रीय वित्तमंत्री से मांग की गई है कि एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी का निर्धारण किया जाए ताकि वे लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें। इसके साथ-साथ कंटेनर भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ताकि बंदरगाहों तक आसानी से सामान भेजा जा सके। राज्यों को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के दिए जाने वाले कैपिटल एक्सपैंस की राशि को बढ़ाए जाने की मांग भी की गई है। हरियाणा सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपये दिए जाने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, उन्हें ऋण दिए जा रहे हैं, फसलों की खरीद समय पर हो रही है। 14 फसलों को हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीद रही है। लगभग 600 एफपीओ हरियाणा में खुल चुके हैं, इन्हें 1 हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में अभी तक 7 अत्याधुनिक एकीकृत पैक हाउस खोले जा चुके हैं, इनकी संख्या इस वर्ष में 50 तक किए जाने का लक्ष्य है। मशरूम फॉमिंग, मच्छली पालन, डेयरी फॉर्मिंग जैसे प्रोजेक्ट को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है।

भारत में ओमिक्रोन का कहर, इन राज्यों में बढ़ा केस; लॉकडाउन लगने के आसार

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए स्वरूप 'ओमीक्रोन' के 180 नए मामले सामने आने के बाद, देश में इस स्वरूप के मामले बढ़कर 961 हो गए। ये एक दिन में सामने आए ओमीक्रोन के सर्वाधिक मामले हैं। इनमें से 320 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं। ये मामले 22 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में सामने आए। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली में सबसे अधिक 263 मामले सामने आए और इसके बाद महाराष्ट्र में 252, गुजरात में 97, राजस्थान में 69, केरल में 65 और तेलंगाना में 62 मामले सामने आए हैं। मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में एक दिन में कोविड-19 के 13,154 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,48,22,040 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 82,402 हो गई। 268 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,80,860 हो गई है। देश में 49 दिन बाद कोविड-19 के 13 हजार से अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं। इससे पहले, 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण के 13,091 नए मामले सामने आए थे।

आंकड़ों के अनुसार, देश में लगातार 63 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 15 हजार से कम हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 82,402 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.24 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 5,400 की वृद्धि दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.38 प्रतिशत है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दैनिक संक्रमण दर 1.10 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले 87 दिन से दो प्रतिशत से कम है। साप्ताहिक संक्रमण दर 0.76 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले 46 दिन से एक प्रतिशत से कम है। देश में अभी तक कुल 3,42,58,778 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.38 प्रतिशत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 143.83 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत के जो 268 मामले सामने आए हैं, उनमें से 211 मामले केरल और 20 मामले महाराष्ट्र में सामने आए। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल 4,80,860 लोगों की मौत संक्रमण से हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,41,496, केरल के 47,277, कर्नाटक के 38,324, तमिलनाडु के 36,758, दिल्ली के 25,107, उत्तर प्रदेश के 22,915 और पश्चिम बंगाल के 19,745 लोग थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक

जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है।

कॉमेडी किंग भारती सिंह ने दिखाया Baby bump, चाहती हैं due date तक काम करना

अपनी कॉमेडी से सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली कॉमेडी किंग भारती सिंह (Bharti Singh) जल्द ही मां बनने वाली हैं और वें सोशल मीडिया पर अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट (Bharti flaunting baby bump) करती हुई नजर आ रही हैं. हाल ही में भारती ने एक पोस्ट शेयर (Bharti instagram post) की है जिसमें वें अपना बेबी बम्प शो कर रही हैं. भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया (Haarsh Limbachiyaa) अपने बच्चे का बेसब्री से काफी लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं जो अप्रैल के महीने में आने वाला है. भारती ने अपनी प्रेगनेंसी (Bharti Singh pregnancy news) की न्यूज़ बहुत पहले ही अपने फैंस को दे दी थी. अब सभी लोग बस नन्हा मेहमान आने का इंतजार कर रहे हैं. भारती फिलहाल पांच महीने प्रेगनेंट (Bharti z months pregnant) है. ऐसे में वह अपने इस दौर को काफी एंजॉय कर रही हैं और साथ ही काम भी कर रही हैं.

आपको बता दें भारती ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वें अपनी डिलीवरी डेट (Bharti delivery date) के अंत तक काम करना चाहती हैं ताकि उनकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए. वो नहीं चाहती है कि डिलीवरी के समय उनको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े. आपको बता दें भारती के द्वारा साझा की गई तस्वीर में उन्होंने रेड ड्रेस और सैंटा कैप पहना हुआ है. इस तस्वीर को शेयर कर भारती ने कैप्शन में लिखा, सैंटा आएगा या सैंटी? आपको क्या लगता है जल्दी कॉमेंट में बताओ. भारती और हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa) अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और इनका ये उतावलापन उनकी हर पोस्ट में झलकता है.

खैर आपको बता दें भारती ने कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वायरल वीडियो (Bharti viral video) में भारती सिंह अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही थी. भारती ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वो एक के बाद एक कई ड्रेसेस को बदलती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर कर अदाकारा ने लिखा है, बहुत मजा आ रहा है, मम्मी बनने में.

अक्षय कुमार ने सबको पीछे छोड़ा, इतनी लेते हैं फीस

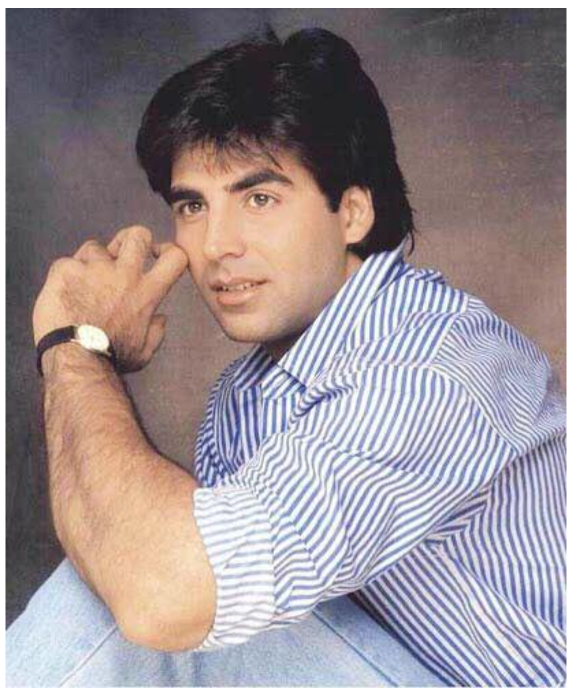

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी फिल्मों के चलते अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय तो बने रहते हैं. लेकिन एक्टर को लेकर एक खबर आ रही है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खीच लिया है. अक्षय कुमार अपनी फिल्मों को लेकर छाए हुए हैं. उन्होंने एक से बढ़कर हिट फिल्में देकर ये साबित कर दिया कि वो भी अच्छी फीस के हकदार हैं. तो यह बात हम आपसे साझा कर दें कि एक्टर को एक फिल्म में 150 करोड़ रूपए दिए जाएंगे. यह बाद एक मीडिया संस्थान के जरिए सामने आई है.

आपको बता दें, केआरके के एक ट्वीट के अनुसार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने वासु भगनानी के बैनर तले बन रही एक मेगा बजट फिल्म साइन की है, जिसे अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) बनाएंगे और इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार (Akshay Kumar)ने 150 करोड़ चार्ज किए हैं. अगर ये खबर सही होती है तो अक्षय कुमार ने फीस के मामले में खान सुपरस्टार्स को भी पछाड़ दिया है.

फिल्म जर्सी फेम मृणाल ठाकुर आखिर क्यों रोया करती थी रातों को ?

बॉलीवुड में टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे जरूर हैं. लेकिन पहचान तो कुछ लोगों को ही मिली है, उनमें से एक हैं टीवी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) जिन्होंने कम समय में एक बड़ी पहचान बना ली है. लेकिन इन सब के पीछे कितनी मेहनत लगी है यह तो कोई नहीं जानता है. तो आज हम एक्ट्रेस (Mrunal Thakur)के इंटरव्यू के जरिए आप तक इस बात की जानकारी पहुंचाएंगे, जो उनके फैंस में जानने की तमन्ना लंबे समय से है. फिल्म इंडस्ट्री में उंची उड़ान भरने वाली एक्ट्रेस में मृणाल ठाकुर Mrunal Thakur का नाम भी शुमार है.

Mrunal Thakur ने साझा किया अपना दु:ख

आपको बता दें, मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur)का करियर जितना देखने में प्यारा लगता है उतना ही पेचीदा था. मृणाल (Mrunal Thakur)ने अपने करियर में आगे बढ़ते समय काफी ठोकरे खाई हैं और आंसू भी खूब बहाए हैं, जिसका खुलासा खुद मृणाल (Mrunal Thakur) ने मीडिया के सामने किया है. उन्होंने बताया की लोग उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, जिसे देखने के बाद वो रातों को रोया करती थीं. इस समय मृणाल ठाकुर और शाहिद कपूर (Shahid kapoor) अपनी आने वाली फिल्म जर्सी (Jersey) को प्रोमोट करने में लगे हुए हैं. वो आए दिन अपनी फिल्म को प्रमोट करते दिखाई देते हैं.

बतादें, इसी बीच में मृणाल ने (Mrunal Thakur)एक इंटरव्यू में बात करने के दौरान बताया कि जब मैं अपने करियर शुरू कर रही थी, तो कई बार मेरे साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता था जिसे देख मैं घर पहुंच कर खूब रोया करती थी. मैंने अपने माता-पिता से बात की और उन्हें बताया कि मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उन्होंने कहा, मृणाल (Mrunal Thakur)10 साल के बाद के बारे में सोचो लोग आपकी तरफ देखेंगे और इतना मोटिवेट होंगे और कहेंगे कि अगर यह लड़की कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूं यार. वहीं मृणाल ने आगे कहा- मैं अपने पेरैंटस की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैंने महेनत करनी सीखी है और सिखाया है कैसे महेनत से चीज़ कमाकर जीती जाती है.

पंजाबी कैटरीना कैफ उर्फ शहनाज़ गिल ने अपनी पंजाबी पर कही ऐसी बात, लोग कर रहे चर्चा

एक्ट्रेस शहनाज़ गिल (Shehnaaz Gill) अब अपने प्यार सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) को धीरे-धीरे भुलाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं. शहनाज़ अब पहले की तरह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हो गई हैं. वो लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं. इस बीच हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक्ट्रेस अपनी पंजाबी एक्सेंट पर बात करती नज़र आ रही हैं. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. साथ ही लोग इस पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि फिलहाल प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेंड चल रहा है. जिसमें अंग्रेजी के कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, जिसे यूज़र को अपने अलग अंदाज़ में बोलना होता है. शहनाज़ (Shehnaaz Gill) ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए वीडियो बनाया है. जिसे उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस अंग्रेजी के शब्दों को पंजाबी भाषा में बोलती नज़र आती हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, मेरी पंजाबी एक्सेंट बहुत सेक्सी है... शहनाज़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो.

बता दें कि इससे पहले भी एक्ट्रेस (Shehnaaz Gill) का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा था. जिसमें शहनाज़ पार्टी में डांस करती नज़र आई थी. एक्ट्रेस अपने दोस्त कौशल जोशी की सगाई में पहुंची थी. जहां उनके साथ कश्मीरा शाह, परितोष त्रिपाठी और जॉर्जिया एंड्रियानी भी पहुंचे थे. इसी दौरान सबके साथ एक्ट्रेस भी डांस करने लगती हैं. उनका ये वीडियो सामने आने के बाद उनके बिग बॉस को-कंटेस्टेंट असीम रियाज़ का एक ट्वीट सामने आया था.

जिसमें असीम ने लिखा था, हाल ही में कुछ डांसिंग क्लिप्स देखें...सच में लोग अपने प्यार को काफी जल्दी भूल गए. क्या बात, क्या बात.....#Newworld. असीम का ये ट्वीट आने पर बवाल मच गया. लोगों को लगा कि वे शहनाज़ पर हमला बोल रहे हैं. हालांकि, काफी हंगामा होने पर असीम ने ये साफ किया कि उन्होंने ये ट्वीट अपने किसी दोस्त के लिए लिखा था, न कि उनके लिए जिनके बारे में लोग सोच रहे हैं.

चौरी–चौरा जन क्रांति पर आधारित है फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी चौरा'

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक कहानियों और अमर सेनानी क्रांतिकारियों के संघर्ष पर फिल्म बनाना फिल्मकारों का पसंदीदा विषय रहा है। यह सिलसिला फिल्म आनंद मठ से लेकर अब तक बदस्तूर जारी है। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, गांधी जी और सेरा नायडू समेत विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक घटनाओं आदि को फिल्मी परदे पर उतारने का कार्य अब भी फिल्मकारों को खूब लुभाता है। अभिनेता मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा से लेकर सनी देओल, अजय देवगन, चिरंजीवी और अभिषेक बच्चन आदि सितारे इन ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा बन चुके हैं।

हाल ही में इस फेहरिश्त में एक और फिल्म शामिल हो गई है, यह है चौरी चौरा जन क्रांति पर आधारित '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा'। सांसद और प्रख्यात अभिनेता रविकिशन इस फिल्म में प्रमुख किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग सौ दिवसीय शेड्यूल में बीते दिनों में गोरखपुर और आस-पास के क्षेत्रों में की गई। फिल्मकार अभिक भानू निर्देशित और रंगमंच से जुड़े रविशंकर खरे निर्मित इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य चल रहा है। चौरी-चौरा जन क्रांति की ऐतिहासिक घटना और उसमें शामिल अमर सेनानियों की शौर्य गाथा इस फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' के माध्यम से अब शीघ्र ही जन-जन तक पहुंचेगी।

सांसद-अभिनेता रविकिशन की है फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका

गोरखपुर से सांसद और प्रख्यात अभिनेता रविकिशन '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं रविकिशन अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित ऐतिहासिक स्थान और विषय पर आधारित इस फिल्म को लेकर खासे उत्साहित हैं। फिल्म के निर्माता रविशंकर खरे ने बताया कि रवि किशन इस फिल्म में चौरी-चौरा जनक्रांति के प्रमुख नायकों में से एक भगवान अहीर के किरदार में हैं। श्री खरे ने बताया कि हमारी पटकथा के अनुसार फिल्म में कुल 58 महत्वपूर्ण पात्र कहानी के केंद्र में हैं।

सत्याग्रही भगवान अहीर के उत्पीड़न से पनपी थी जन विद्रोह की ज्वाला

ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि चौरी चौरा जन विद्रोह की शुरूआत सेना छोड़ असहयोग आंदोलन में सत्याग्रही बने भगवान अहीर पर फिरंगी पुलिस के उत्पीड़न के बाद हुई थी। एक फरवरी 1922 को फिरंगी पुलिस के दारोगा ने असहयोग आंदोलन में सक्रियता से क्रुद्ध होकर भगवान अहीर की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। भगवान अहीर अपने ऊपर हुई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से डरे-डिगे नहीं। भगवान अहीर और श्याम सुन्दर मिश्र के साथ अन्य कई साथी सत्याग्रहियों के नेतृत्व में 4 फरवरी 1922 को जुटे सत्याग्रहियों (ग्रामीणों-किसानों) पर फिरंगी पुलिस ने गोलियां खत्म होने तक फायरिंग की थी, जिसमें सैंकड़ों निहत्थे सत्याग्रिहयों की जान चली गई थी। भड़के सत्याग्रहियों ने प्रतिकार स्वरूप चौकी फूंकने की घटना को अंजाम दिया था। चौकी में हुई आगजनी की घटना में दरोगा गुप्तेश्वर सिंह समेत 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी।

बाबा राघव दास की पहल पर महामना ने की सत्याग्रहियों की पैरवी

इस घटना से बौखलाई फिरंगी प्रशासन ने चौरा-चौरी में मार्शल-लॉ लगा दिया और बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए आसपास के पूरे क्षेत्र में जमकर कहर बरपाया। हजारों ग्रामीणों-किसानों को हिसासत में लेकर उन पर अत्याचार किया। ज्ञात-अज्ञात हजारों सत्याग्रहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सैंकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1000 लोगों की पहचान की गयी, जिसमें से 288 स्वयं सेवकों को हिरासत में ले लिया गया। फिरंगी पुलिस के उत्पीड़न से 6 सत्याग्रहियों की मौत हिरासत में ही हो गयी। सत्याग्रहियों को बचाने, उनकी पैरोकारी करने के लिए बाबा राघव दास ने आगे आने की हिम्मत दिखाई। बाबा राघव दास की पहल पर ही महामना मदन मोहन मालवीय ने सत्याग्रहियों की पैरवी की थी।

'चौरी-चौरा जन विद्रोह' को सरकारों, इतिहासकारों ने छिपाया-दबाया

फिल्म के निर्माता रविशंकर खरे कहते हैं कि ब्रिटिश अत्याचारों से पनपे आक्रोश के बाद हुई जन क्रांति की इस घटना को स्वतंत्रता के बाद भी सरकारों ने भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया। हमारे अधिकांश इतिहासकार और लेखक भी इस विषय पर उदासीन ही रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई पहल के बाद इतिहास के पन्नों पर चढ़ी धूल हटाने का कार्य शुरू हुआ और कुछेक लेखकों ने 'चौरी-चौरा' जन क्रांति पर अपनी लेखनी चलाने की हिम्मत दिखाई है। इसी क्रम में स्वयं उन्होंने भी फिल्मकार अभिक भानू संग पहल करते हुए अपनी टीम के साथ स्वाधीनता संग्राम की इस महत्वपूर्ण घटना पर फिल्म बनाने की योजना को साकार करने का बीड़ा उठाया। श्री खरे ने कहा कि इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी पूरी टीम का प्रयास किया है कि चौरी-चौरा जन क्रांति की घटना और उसमें शामिल अमर सेनानियों की शौर्य गाथा को फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाए।

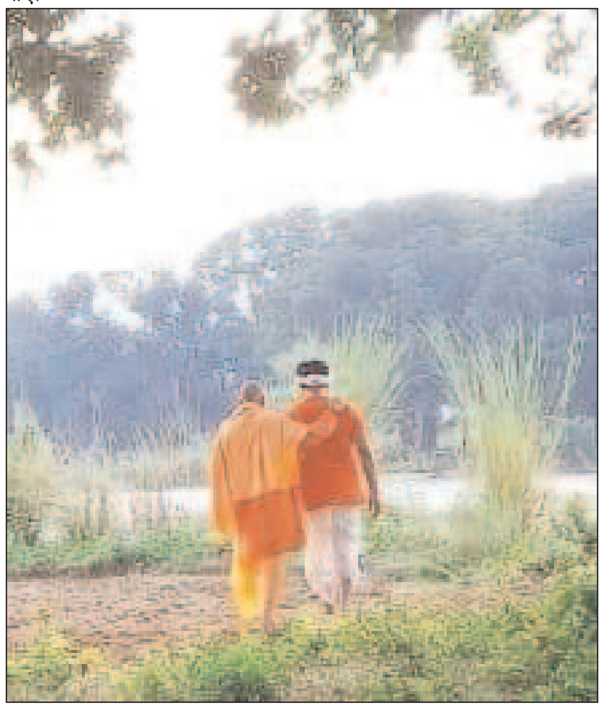

चौरी-चौरा की घटना पर बनने वाली यह है पहली हिन्दी फिल्म

चौरी-चौरा की घटना पर बनने वाली यह पहली हिन्दी फिल्म है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने की तैयारियों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' को गोरखपुर जनपद के ऐतिहासिक कस्बे चौरी चौरा समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और देवरिया आदि प्रमुख स्थानों पर फिल्माया गया। फिल्म के निर्माता रविशंकर खरे ने बताया कि '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' के निर्माण से संबंधित विभिन्न पक्षों के लिए जहां प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के ही तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई हैं, वहीं स्थानीय कलाकारों को काम करने का मौका भी दिया गया।

कथा-पटकथा तैयार करने से पूर्व लेखन टीम ने किया है व्यापक शोध

रविशंकर ने बताया कि फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' की कहानी लिखने और फिल्मांकन के लिए पटकथा (स्क्रिप्ट) तैयार करने से पूर्व इस ऐतिहासिक घटना को लेकर हमारी टीम ने व्यापक शोध किया है। इसके उपरांत ही फिल्म की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया गया। श्री खरे बताते हैं कि स्क्रिप्ट तैयार करने में प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी की पुस्तक 'चौरी चौरा एक पूर्णावलोकन राष्ट्रीय आयाम की एक स्थानीय घटना' के साथ ही कई अन्य प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकों के स्रोत को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न ऐतिहासिक बिन्दुओं का तथ्यात्मक अध्ययन किया गया है। श्री खरे ने बताया कि इस स्क्रिप्ट को पूरा करने में 8 महीने का समय लगा।

यह है ऐतिहासिक फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' की टीम

रविशंकर खरे ने सरयू विजन के बैनर तले बनी इस ऐतिहासिक फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' की निर्माण टीम के बारे में बताया कि सह निर्माता अंजू खरे हैं। दो दशक से मीडिया और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय मीडिया प्रबंधक, फिल्मकार, पत्रकार, गौरव शंकर खरे क्रिएटिव प्रोड्यूसर के साथ ही मीडिया प्रमोशन का दायित्व भी निभा रहे हैं। अभिक भानू निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग 100 दिन के नियमित शेड्यूल पूरी की गई है।

पटकथा लेखन में इतिहासविद् प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी और रंगमंच से जुड़े रविशंकर खरे के साथ मनोज शर्मा, अंजू खरे, अनुराधा सूर्यवंशी, पवन पांडे, सचिन अवचिटे, गौरव गोविंद, योगेंद्र बहादुर खरे, सुषमा, निशिगंधा, दीपा मुखर्जी और विश्वनाथ सहित करीब 20 लेखकों की टीम शामिल रही। फिल्म की पटकथा को अंतिम रूप देने में रवि शंकर खरे, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव, केशव, टीना गुप्ता, चैतन्यसिंह गोहिल और छवि गौरांग ने खासी मेहनत की है। फिल्मांकन की कमान फोटोग्राफी के निर्देशक मनोज गुप्ता के हाथ रही। किसी भी ऐतिहासिक फिल्म में कला पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य चल रहा है। फिल्म एडिटर अरुण शेखर की देखरेख में संपादन का कार्य किया जा रहा है। श्री खरे का दावा है कि '1922 प्रतिकार चौरी चौरा' ऐसी पहली ऐतिहासिक फिल्म होगी, जिसे वैश्विक स्तर पर भव्यता के साथ रिलीज करने की योजना है।

यदि आप कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो रोज सुबह खाली पेट लौकी का एक गिलास जूस पीना ना भूलें। लौकी का जूस पीने से मोटापा दूर होता है, पित्त कंट्रोल होती है, दिल की बीमारी और हाई बीपी की समस्या से छुटकारा मिलता है। लौकी का जूस बनाने के बाद इसे एक बार जरूर चख कर देख लें। लौकी में कई गुण होते हैं जो शरीर के कई रोगों को दूर करते हैं। लौकी में 12 प्रतिशत तक पानी होता है और बाकी फाइबर होता है। भारत में लाखों लोग स्वस्थ रहने के लिये रोज़ लौकी का जूस पीते हैं। गर्मियों में इसका जूस पीने से शरीर को काफी लाभ मिलते हैं।

यदि आप कभी बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो रोज सुबह खाली पेट इसका एक गिलास पीना ना भूलें। लौकी का जूस जिस तरह से फायदा पहुंचाता है ठीक उसी तरह से इसको पीते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिये। लौकी का जूस बनाने के बाद इसे एक बार जरूर चख कर देख लें कि कहीं यह कड़वा तो नहीं। क्योंकि अगर यह कड़वा है तो यह पेट में गैस और अपच पैदा करेगा। आइए अब जानते हैं इसे बनाने की विधि और कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में....

लौकी के जूस की रेसिपी-

लौकी- 250 या 300 ग्राम
पुदीने की पत्ती- 5-6
जीरा पाउडर- 1/2 टीस्पून
काली मिर्च पाउडर - चुटकीभर
नमक- स्वाद अनुसार

जूस बनाने की विधि

सबसे पहले लौकी को छील कर धो लें। फिर उसे छोटे पीस में काटें। अब एक ब्लेंडर में लौकी के टुकड़े डाल कर साथ में पुदीने की पत्ती मिलाएं और चलाएं। जब जूस बन जाए तब उसमें जीरा पावडर, नमक और कली मिर्च पावडर डालें। इसे अच्छी तरह से चलाएं और बर्फ डाल कर सर्व करें।

लौकी के जूस को पीने का फायदा

मोटापा घटाए

वे लोग जो वजन घटाना चाहते हैं उनके लिये लौकी का जूस काफी फायदेमंद होता है। इस जूस को नियमित पीने से भूख कंट्रोल रहती है। इस जूस में ढेर सारे विटामिन, पोटैशियम और आयरन भारी मात्रा में पाया जाता है। आप इसे रोज सुबह खाली पेट पिएंगे तो फायदा होगा।

पाचन क्रिया सुधारे और कब्ज दूर करे

लौकी में ढेर सारा घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कि उसमें मौजूद ढेर सारे पानी के साथ मिल कर पाचन क्रिया को आसान बनाता है। इस जूस को नियमित पीने से कब्ज ठीक होता है तथा एसिडिटी में आराम मिलता है।

बॉडी हीट कम करता है

अगर आपकी बॉडी में हीट है, जिसके चलते सिर में दर्द या फिर अपच होता है तो लौकी का जूस जरूर पीना चाहिये। लौकी के जूस में अदरक मिला कर पिएं तो ज्यादा फायदा होगा।

हाई ब्लड प्रेशर कम करे

हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन चुकी है। लौकी के जूस में पोटैशियम अधिक पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिये जाना जाता है।

सफलता के नए सोपान पार कर रहे हैं अभिनेता गौरव शंकर खरे

बाबा गौरक्षनाथ की नगरी गौरखपुर में जन्मे फिल्मकार, प्रबंधन विशेषज्ञ, अभिनेता, पत्रकार, गौरव शंकर खरे दिन-प्रतिदिन सफलता के नए सोपान पार कर रहे हैं। गौरव का परिवार विगत कई पीढ़ियों से राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति मुखर है और राष्ट्रवाद के प्रचार-प्रसार में संलग्न है। उनके बाबा लक्ष्मी शंकर खरे, गोरखपुर नगर में जनसंघ और भाजपा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेई और गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैद्यनाथ जी के साथ भी संगठनात्मक कार्य किया। वे गोरखपुर नगर निगम के प्रथम चेयरमैन बने।

गौरव के पिता रविशंकर खरे, वर्तमान में भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के अध्यक्ष के रूप में रंगमच के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। रविशंकर खरे ने संस्कार भारती के अखिल भारतीय नाट्य संयोजक होने के साथ ही दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रहने के दौरान अनेक नाट्य रचनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर मंचन कराया, विभिन्न महोत्सव आयोजित कराए। रविशंकर खरे, फिल्मकार अभिक भानू निर्देशित जलियांवाला बाग नरसंहार की तरह उत्तर प्रदेश के चौरी-चौरा में हुई घटना के बाद भड़की जनक्रांति पर आधारित फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' से प्रस्तोता के रूप में जुड़े हुए हैं।

गौरव शंकर खरे भी अपने पूर्वजों की परिपाटी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गौरखपुर से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत स्नातक की पढ़ाई दिल्ली में की। अपनी रूचि के अनुरूप गौरव शंकर खरे ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा स्थित प्रख्यात फिल्म संस्थान एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन (आफ्ट) से फिल्म निर्माण विधा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट में अपना सृजनात्मक योगदान दिया। वर्ष 2003 में उत्कृष्ट निर्देशन के लिए उन्हें 'बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड' से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दिया।

लिखने-पढ़ने में विशेष रूचि रखने वाले गौरव शंकर खरे का छात्र जीवन से ही मीडिया के साथ निकटतम संबंध रहा है। शिक्षा प्राप्ति के बाद गौरव शंकर खरे ने विज्ञापन के क्षेत्र में सक्रिय संस्थान 'ऊषककाल' के साथ कार्य किया। इसके बाद टीवी चैनल 'सहारा समय' में बतौर निर्माता अपनी सेवाएं दीं। तदोपरांत दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका आब्जर्वर डॉन से जुड़े रहे और प्रबंधन पक्ष संभाला। वर्तमान में राष्ट्रवादी पत्रिका 'गौरवशाली भारत' और 'हिन्द पथिक' के साथ पत्रकार के रूप में सक्रिय हैं। साथ ही अभिनय और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति अंकित करने में जुटे हुए हैं।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी गौरव शंकर खरे चौरी-चौरा जनक्रांति पर आधारित फिल्म '1922 प्रतिकार : चौरी-चौरा' के क्रियेटिव प्रोड्यूसर होने के साथ ही बतौर अभिनेता भी जुड़े हुए हैं। इस फिल्म में वे गोरक्षनाथ पीठ से संबद्ध 'चिंताहावा बाबा जी' की भूमिका निभा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि चिंताहावा बाबा ने स्वाधीनता आन्दोलन में अनेक क्रांतिकारियों के प्रेरक और संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। माना जाता है कि 'चिंताहावा बाबा' गोरक्षनाथ पीठ के महंत दिग्विजय नाथ जी का ही छद्म नाम था।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ चारों खाने चित होने के बाद जो रूट ने बताया, क्यों हारी इंग्लैंड की टीम

एजेंसी, नई दिल्ली। आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज को मेजबान कंगारू टीम ने अपने नाम कर लिया है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली आस्ट्रेलिया की टीम ने पहले तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। तीसरे मैच में इंग्लैंड को दूसरी पारी में 68 रन पर समेटने के साथ टीम ने बाक्सिंग डे टेस्ट मैच में पारी और 14 रन से जीत दर्ज की।

इस मैच और सीरीज की हार को लेकर जो रूट ने बयान दिया है और बताया है कि उनकी टीम ने एशेज सीरीज में कहां क्या गलती की और उनकी टीम मजबूती के साथ दो मैच खेलने उतरेगी। मेलबर्न टेस्ट मैच में शर्मनाक हार के बाद कप्तान जो रूट ने कहा, जो है सो है। हम कुछ समय के लिए इस तरह के माहौल से निपटने के लिए आए हैं। आस्ट्रेलिया को जीत का श्रेय जाना चाहिए।

उन्होंने हमें कल रात बुरी तरह से परेशान किया। और उन्होंने हमें इस टेस्ट मैच में, वास्तव में अब तक की सीरीज की सबसे भयंकर मात दी है। हमें अभी काफी मेहनत करनी है और आखिरी दो मैचों में मजबूती से वापसी करनी है। कोविड का खतरा आदर्श नहीं था। एमसीजी टेस्ट के दूसरे दिन से पहले इंग्लैंड की टीम के सपोर्ट स्टाफ के दो सदस्य और परिवार के दो सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए थ। एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारकर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंचे कप्तान जो रूट ने आगे कहा, ष्जिस तरह से हमने अपने क्रिकेट के बारे में जाना, खासकर हमारी गेंदबाजी कल बेहतरीन थी। इसे मैनेज करने और इस खेल में खुद को मौका देने का श्रेय गेंदबाजों को जाता है। हमें बस चीजों को अधिक समय तक करना है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हम जानते हैं कि हमें कहां काम करना है और हमें बहुत मजबूत रहना है और यह सुनिश्चित करना है कि हम अगले दो मैचों को इस दौरे से कुछ लेने के वास्तविक अवसर के रूप में देखें।

आस्ट्रेलिया की टीम डब्लयूटीसी की अंकतालिका में बनी नंबर वन, किस स्थान पर है टीम इंडिया

एजेंसी, नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आइसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की अंकतालिका जारी कर दी है। आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे मैच में मेजबान कंगारू टीम को जीत मिली और टीम डब्लयूटीसी की अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। वहीं, इंग्लैंड की टीम अभी भी सातवें स्थान पर है। इंग्लैंड के खाते में सिर्फ 6 अंक हैं और भारतीय टीम अभी भी अच्छी स्थिति में है। आस्ट्रेलिया की टीम ने पांच मैचों की एशेज सीरीज के पहले तीन मुकाबले जीत लिए हैं। एक मैच जीतने पर 12 अंक मिलते हैं और इस तरह टीम के खाते में 36 अंक हो गए हैं और जीत प्रतिशत भी 100 है। इसलिए आस्ट्रेलिया की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के 2023 के चक्र की अंकतालिका में शीर्ष पर है। इस मुकाबले से पहले श्रीलंका की टीम पहले स्थान पर थी, लेकिन अब श्रीलंका की टीम दूसरे स्थान पर है, जिसके खाते में 24 अंक हैं। तीसरे पायदान पर पाकिस्तान की टीम है, जिसने अपने चार में से 3 मुकाबले जीते हैं और टीम के खाते में 36 अंक हैं। वहीं, भारतीय टीम 42 अंक अब तक अर्जित कर चुकी है, लेकिन टीम ने 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें तीन जीते हैं, दो मुकाबले ड्रा रहे हैं और मुकाबला टीम ने गंवाया है। इतना ही नहीं, चौथे नंबर पर विराजमान भारतीय टीम के दो अंक पेनाल्टी ओवरों के कारण काट लिए गए हैं। यही वजह है कि अब टीम का जीत प्रतिशत 58.33 है। इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर वेस्टइंडीज की टीम है, जिसने 4 मैचों में सिर्फएक मैच जीता है और टीम के खाते में कुल 12 अंक हैं। छठे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसने विश्व टेस्ट चौंपियन बनने के बाद दो टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें एक मुकाबला ड्रा रहा है। इसके एवज में टीम को 4 अंक मिले हैं। एक मुकाबला भारत के खिलाफ कीवी टीम हार भी चुकी है।

आइसीसी मेन्स टेस्ट प्लेयर आफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चार खिलाड़ी चयनित, एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली। आइसीसी ने मेन्स टेस्ट प्लेयर आफद ईयर अवार्ड 2021 के लिए चार खिलाड़ियों का चयन किया है। इन चारों खिलाड़ियों में एक मात्र भारतीय खिलाड़ी आर अश्विन को शामिल किया गया। आर अश्विन के अलावा अन्य तीन खिलाड़ियों में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान जो रूट, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन और श्रीलंका क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान दिमुश करुणारत्ने शामिल हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन चारों खिलाड़ियों में से किसे आइपीएल मेस्ट टेस्ट प्लेयर आफ द ईयर 2021 का खिताब मिलता है। साल 2021 में टेस्ट क्रिकेट में अगर इन चारों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो जो रूट ने 15 टेस्ट मैचों में 61 की औसत से 1708 रन बनाए हैं जिसमें 6 शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। वहीं आर अश्विन की बात करें तो उन्होंने अब तक इस साल 8 टेस्ट मैचों में 16.33 की औसत से 52 विकेट (इसमें सेंचुरियन टेस्ट के विकेट व रन शामिल नहीं हैं) लिए हैं। वहीं गेंद के साथ-साथ अश्विन ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में 337 रन भी बनाए हैं जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच की दूसरी पारी में लगाया गया शतक भी शामिल है। रूट और अश्विन के अलावा बात अगर काइल जैमीसन के प्रदर्शन की हो तो न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज के लिए ये साल काफी अच्छा गुजरा है। उन्होंने हाल ही में अपने 9 टेस्ट मैचों में 50 विकेट पूरे किए हैं और वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर आफद मैच भी चुना गया था। भारत के खिलाफ उन्होंने इस मैच में 7 विकेट लिए थे और 16 गेंदों पर तेज 21 रन बनाते हुए टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं इस साल 5 टेस्ट मैचों में उन्होंने 27 विकेट भी लिए हैं। वहीं दिमुथ करुणारत्ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने के मामले में निरंतर रहे हैं। उन्होंने इस साल 9 टेस्ट मैचों में 69.38 की औसत से 902 रन बनाए हैं और चार शतक शामिल है।

इस बड़ी वजह से सेलेक्टर्स नहीं कर रहे हैं वनडे टीम का चयन, लेकिन इन दो नए खिलाड़ियों का चुना जाना तय

एजेंसी, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वनडे टीम अब इस महीने के अंत तक चुनी जा सकती है क्योंकि भारत के वनडे व टी20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने से ठीक पहले हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद वह एनसीए में रिहैबिलिटेशन के दौर से गुजर रहे हैं। विजय हजारे ट्राफी समाप्त होने के तुरंत बाद चयनकर्ताओं के मिलने और टीम चुनने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि रोहित को अभी पूरी तरह फिट होने के लिए कुछ और समय की जरूरत है। इसके अलावा, यह भी पहले बताया गया था कि अगर वह इस वनडे सीरीज को मिस करते हैं, तो केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका में एकदिवसीय मैचों में कप्तानी कर सकते हैं। बीसीसीआइ अधिकारी ने टीम चयन में देरी की खबर की पुष्टि की। उन्होंने यह भी बताया कि आलराउंडर रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वनडे के लिए टीम चयन की बैठक पहले टेस्ट के बाद होगी। लेकिन बीसीसीआइ को अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है। रोहित फिट होने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन हैमस्ट्रिंग की चोट अन्य चोटों से थोड़ी अलग है। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि यह पता चला है कि रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। रोहित के बारे में, चयन तिथि के करीब फैसला लिया जाएगा।

बीसीसीआइ अधिकारी ने आगे कहा कि जहां तक खिलाड़ियों के चयन का सवाल है, रुतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर को चुना जाना तय है, जबकि सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को भी विजय हजारे ट्रॉफी में खराब फार्म के बावजूद वनडे टीम में बरकरार रखा जाएगा। हाल ही में घरेलू एक दिवसीय टूर्नामेंट में अपने हिटिंग कौशल की वजह से शाहरुख खान के नाम पर चर्चा होने की भी संभावना है। वहीं पूरी तरह से फिट नहीं होने के बावजूद रोहित शर्मा के चुने जाने की भी संभावना है। हालांकि, उन्हें 19 जनवरी को खेले जाने वाले पहले वनडे से पहले अपनी फिटनेस हासिल करने का मौका दिया जाएगा, जो अभी तीन सप्ताह दूर है।

एशेज टेस्ट सीरीज गंवाने पर इंग्लैंड के आल-राउंडर ने अपनी टीम को लेकर दे दिया बेहद बोल्ड बयान

एजेंसी, नई दिल्ली। एशेज टेस्ट सीरीज 2021-22 के पहले तीन मुकाबले लगातार जीतकर मेजबान टीम आस्ट्रेलिया ने खिताब पर कब्जा कर लिया। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में आस्ट्रेलिया की टीम ने अब 3-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है साथ ही ये सीरीज भी अपने नाम की। इंग्लैंड की टीम को बाक्सिंग डे टेस्ट मैच में पारी और 14 से हार का सामना करना पड़ा और इस मैच में इंग्लैंड की बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही। इंग्लैंड की इस हार के बाद इस टीम के आलराउंडर मोइन अली ने टीम के प्रदर्शन को लेकर बहुत ही बोल्ड प्रतिक्रिया दी। मोइन अली ने इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के बाद कहा कि जिस तरह का प्रदर्शन इस टीम ने किया है उससे साफ हो जाता है कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त आस्ट्रेलिया से काफी पीछे है। हालांकि मोइन अली का ये मानना है कि एशेज शुरू होने से पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। बीटी स्पोर्ट्स के बात करते हुए मोइन अली ने कहा कि आस्ट्रेलिया कि टीम इंग्लैंड से इस वक्त काफी आगे है और हम तीनों टेस्ट मैच में उनसे काफी पीछे रह गए। मुझे नहीं लगता है कि इस टेस्ट सीरीज से पहले इतना बड़ा गैप था, लेकिन इन हार के बाद ये गैप काफी बड़ा हो गया है। मोइन अली ने आगे कहा कि मुझे याह नहीं है कि इन तीनों मैचों में हमने कितने सेशन अपने नाम किए। टेस्ट क्रिकेट में सफल होने के लिए आपको तकनीक, अनुभव और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेरा ऐसा नहीं कह रहा कि हमारी टीम कड़ी मेहनत नहीं करती, लेकिन सही चीजों पर मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की बल्लेबाजी काफी खराब रही थी और पहली पारी में इस टीम ने जहां 185 रन बनाए थे तो वहीं दूसरी पारी में ये टीम सिर्फ 68 रनों पर ही सिमट गई।

पूर्व भारतीय आलराउंडर इरफान पठान दूसरी बार पिता बने, बेटे का नाम रखा सुलेमान खान

एजेंसी, नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व आलराउंडर इरफान पठान दूसरी बार पिता बने। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उनकी पत्नी ने उनके दूसरे बेटे को जन्म दिया और इसका नाम उन्होंने सुलेमान खान रखा है।

इरफान पठान ने ट्विट करते हुए लिखा कि उनकी पत्नी सफा और बेटा दोनों पूरी तरह से ठीक हैं और उन्होंने अपने बेटे के साथ की एक तस्वीर भी शेयर की। आपको बता दें कि इरफान पठान ने कई साल तक भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो कमेंटेटर व क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में नजर आते हैं। भारत के लिए उन्होंने 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 टी20 मैच खेले थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 100 विकेट लिए थे तो वहीं उन्होंने वनडे क्रिकेट में 173 विकेट हासिल किए थे। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम पर 28 विकेट दर्ज है। टेस्ट क्रिकेट में इरफान पठान ने 31.57 की औसत से 1105 रन बनाए थे तो वहीं वनडे क्रिकेट में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 1544 रन बनाए थे। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 172 रन बनाए थे। साल 2007 में जब टीम इंडिया ने पहले बार टी20 वर्ल्ड कप एम एस धौनी की कप्तानी में जीता था तब इरफान पठान उस टीम का हिस्सा थे और फाइनल में काफी अच्छा प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ किया था। वहीं वो टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से पारी के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने ये उपलब्धि साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की थी। इरफान पठान ने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच वर्ष 2012 में खेला था।